राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 315 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, रविवार ,23 मई 2021, मूल्य रु. 1.50

ब्लैक फंगस पर सरकार उठा रही कदम : स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश में कोरोना महामारी का संकट लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार लोगों को राहत देने के लिए अपने-अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी देश में कोरोना की स्थिति को लेकर लोगों को लगातार जानकारी दे रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केवल सात राज्य ऐसे हैं जहां 10 हजार से अधिक मामले आ रहे हैं और 5- 10 हजार मामलों वाले 6 राज्य हैं। वहीं 6 राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों से देश में सक्रिय मामलों में कमी देखी जा रही है। तीन मई को देश में 17.13 फीसदी सक्रिय मामले थे और अब यह 11.12 फीसदी हो गया है। रिकवरी रेट भी 87.76 फीसदी हो चुकी है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि ब्लैक फंगस के लिए एमफोटेरेसिन-बी जिसकी देश में सीमित उपलब्धता थी, उसे बढ़ाया जा रहा है। 5 अतिरिक्त मैन्युफैक्चर्स का लाइसेंस दिलाने का कार्य किया जा रहा है। अभी जो मैन्युफैक्चर्स हैं, वो भी उत्पादन बढ़ा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लव अग्रवाल ने कहा कि एक लाख से अधिक सक्रिय मामले अब केवल आठ राज्यों में रह गए हैं। 50 हजार से एक लाख के बीच सक्रिय मामले वाले राज्य भी आठ हो गए हैं। 50 हजार से कम सक्रिय मामले वाले 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 2,57,000 मामले दर्ज. किए गए हैं। जबकि 3,57,630 लोग रिकवर हुए हैं। 78 फीसदी नए मामले 10 राज्यों से दर्ज किए जा रहे हैं। सिर्फ 7 राज्यों में प्रतिदिन 10 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक देश में 18.41 करोड़ वैक्सीन की डोज 45 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग, हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। 18-44 आयु वर्ग के लिए 92 लाख के लगभग डोज अब तक उपलब्ध कराई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बच्चों में अगर कोरोना हो भी रहा है तो उनमें हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं। और मृत्यु दर बहुत ही कम है।

बिना स्टॉक सभी के लिए खोल दिया टीकाकरण : सीरम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देशभर में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर सीरम इंस्टिट्यूट ने सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सरकार ने न केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइड लाइन को अनदेखा किया, बल्कि वैक्सीन का स्टॉक किए बगैर सभी के टीकाकरण के लिए इसे खोल दिया गया। सीरम इंस्टिट्यूट के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने बिना आकलन के कितनी वैक्सीन है और कितनी चाहिए वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी दे दी। जाधव ने कहा कि शुरू में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, जिसके लिए 60 करोड़ खुराक की आवश्यकता था, लेकिन सरकार ने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि हमारे पास कितना स्टाक है और कितने समय तक कितना उत्पादन कर सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हम टारगेट तक पहुंचते इससे पहले ही सरकार ने 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन के साथ- साथ 18 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए भी वैक्सीनेशन खोल दिया जबकि सरकार को भी पता था कि हमारे पास वैक्सीन का इतना स्टॉक नहीं है। इस बात से हमें ये सीख मिली की। हमें उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए और उसका न्याय संगत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से त्रस्त है। ऐसे में टीकाकरण पर जोर डालना ही सरकार का एकमात्र काम होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कुछ अलग बयां कर रही है। मई के महीने में देश में टीकाकरण का आंकड़ा घटा है, जो चिंता का विषय बन सकता है। पिछले 40 दिन में वैक्सीनेशन की गति में 50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। जो लक्ष्य रखा गया था उसका 50 फीसदी भी हासिल नहीं हो पाया। अप्रैल में जब संक्रमण ने जोर पकड़ा तो टीकाकरण में तेजी आई थी और दस अप्रैल को 36,59,356 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन इसके बाद लगातार टीकाकरण की संख्या घटने लगी। वहीं 21 मई को 24 घंटों के अंदर 17,97,274 खुराकें लगाई गईं।

मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर नहीं होगा कोई कार्यक्रम : नड्डा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। 30 मई को मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे मौके पर भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं में जश्न का माहौल होता है और वह पूरे उत्साह में रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। भाजपा ने इस बार कोई भी जश्न का कार्यक्रम नहीं करने का निर्णय लिया है। इस बात को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है। अपने पत्र में जेपी नड्डा ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सात साल होने के मौके पर भाजपा जश्न का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। उन्होंने इस मौके पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाने को कहा है।

भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने पार्टी के शासन वाले राज्यों से मोदी नीत केंद्र सरकार के सात साल होने के मौके पर 30 मई को कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए कार्यक्रमों की शुरूआत करने को कहा है। अपने पत्र में नड्डा ने लिखा है कि पिछली एक शताब्दी में कभी भी दुनिया ने इस तरह की त्रासदी नहीं देखी है और ना ही अनुभव की है। कोरोना महामारी से ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। 100 साल के बाद आई इस भीषण महामारी ने हमारे कई अपनों को छीना है। हमारे राष्ट्र व समाज में कई गहरे जख्म दिए हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि दुर्भाग्य से यह विभीषिका इतनी बड़ी है कि अनेक बच्चे अनाथ हो गए हैं। उनके माता-पिता इस महामारी के शिकार हो गए हैं। उनके जीवन में आए इस दुख का एहसास हम सभी को है। उनके भविष्य के लिए सोचना और ठोस कदम उठाना हमारा दायित्व है। ऐसे में इन बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके साथ खड़े होना, उनको हर तरह का संबल देना हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है।

चक्रवात 'यास' से निपटने की तैयारियां तेज, कैबिनेट सचिव ने की अहम बैठक, बोले- स्वास्थ्य सेवाएं न हों प्रभावित

नई दिल्ली । बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से आने वाले साइक्लोन यास के मद्देनजर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट राजीव गौबा ने राष्ट्रपति आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की. बैठक में मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 26 मई को शाम में तूफान यास बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराएगा। तेज बारिश और बवंडर के साथ उस वक्त इस तूफान की स्पीड 155 से 165 किमी/घंटे होगी.

बंगाल, ओडिसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मुख्यसचिव ने बताया कि समुंद्र के तटीय इलाकों को खाली कराने की कोशिश जारी है. प्रभावित इलाकों के लोगों को खाने-पीने के सामान का इंतजाम किया जा रहा. एनडीआरएफ की 65 टीम की तैनाती हो चुकी है और अतिरिक्त 20 टीमें स्टैंड बाई मोड में रखी गई हैं. सेना, नौ सेना और कोस्ट गार्ड के जहाज और एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए गए हैं.

तूफान से निपटने के लिए तैयारियां जारी- तूफान की वजह से कोरोना के मरीजों की चिकित्सा प्रभावित ना हो इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा. कोरोना कैम्प/अस्पतालों में बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध जारी रहे इसका पूरा प्रबंध किया जा रहा. 26 मई को बहुत भीषण चक्रवाती तूफान, बंगाल, ओडिशा के पार जाने की संभावना है.

मौसम विभाग की चेतावनी

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जीके दास ने कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों पर और उसके बाद 26 मई की पूर्वाह्न से हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने और उसके बाद शाम तक बढ़ने की उम्मीद है. क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार को पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना, जिसके 26 मई की सुबह के आसपास एक बहुत भीषण चक्रवाती तूफान और पश्चिम बंगाल, उत्तर ओडिशा और बांग्लादेश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है.

नेपाल की संसद भंग, होंगे मध्यावधि चुनाव

काठमांडू, (एजेंसी)। नेपाल में राजनीतिक उठापटक के बीच राष्ट्रपति ने नेपाल की संसद को भंग कर दिया है। नेपाल में मध्यावधि चुनाव दो चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव 12 और दूसरे चरण का चुनाव 19 नवंबर को होगा। जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद के लिए शेर बहादुर देउबा और केपी शर्मा ओली दोनों के दावों को खारिज कर दिया है। नेपाल में संसद भंग करने का ये फैसल संविधान की अनुछेद 76 (7) के तहत लिया गया है।

दरअसल, गुरुवार को नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम में काफी उठापटक देखने को मिली। नेपाल के विपक्षी दलों और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दोनों ने ही अपना बहुमत साबित करने की इच्छा राष्ट्रपति से जाहिर की। हालांकि, ओली को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करना था। गुरुवार तक विश्वास मत हासिल करने पर अनिच्छा जताने वाले ओली विपक्षी दलों के राष्ट्रपति के पास पहुंचते ही फिर दावा करने पहुंच गए।

नेपाल के विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को 149 सांसदों का समर्थन पत्र सौंपते हुए सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विपक्षी दल नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में सरकार बनाने लिए तैयार हैं।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने शुक्रवार को पांच बजे तक विपक्ष को सरकार बनाने का दावा पेश करने का समय दिया। इस बीच प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली भी अचानक राष्ट्रपति के पास पहुंच गए और उन्होंने 153 सांसद का समर्थन होने का दावा किया। उन्होंने अपनी पार्टी के 121 सदस्यों के साथ ही 32 जनता समाजवादी पार्टी-नेपाल के सांसदों का समर्थन होने का दावा किया है।

कोरोना वेरिएंट को इंडिया से जोड़ने पर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बीजेपी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की कोरोना वायरस के प्रकार वेरिएंट को भारत से जोड़ने के लिए निंदा की और आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है, जिससे देश का अपमान हो रहा है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है और इसके बजाए उसने नकारात्मक राजनीति की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने बातचीत के दौरान भारतीय कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्पष्ट किया है कि वायरस के किसी भी प्रकार का नाम किसी देश के नाम से नहीं जोड़ा जाएगा। जावड़ेकर ने कहा, वह (कमलनाथ) यही नहीं रुके और कहा कि हमारी पहचान मेरा भारत कोविड है यह भारत का अपमान है। कांग्रेस के कई नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। कई नेताओं ने कहा कि यह भारतीय प्रकार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर म्यूकरमाइकोसिस (काला कवक) के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करने और इससे प्रभावित लोगों का निःशुल्क इलाज करने के बारे में जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने विदेशों से भी दवाएं मंगाई हैं और राज्यों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर लोगों के बीच भ्रम एवं भय फैलाने के आरोप लगाए और कहा कि वे तब से ऐसा कर रहे हैं, जब कोविड-19 का घरेलू टीका कोवैक्सीन लॉन्च किया गया था। जावड़ेकर ने कहा कि अब यह दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है, उन्हें यात्रा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यह दूसरे देशों में सूचीबद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, यह प्रक्रिया जारी है और डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के बयान से न केवल देश का अपमान हुआ है बल्कि उसने महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया है। जावड़ेकर ने कहा, सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस इस तरह की नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है और उन्होंने कमलनाथ के बयान की निंदा क्यों नहीं की है।

देश में बढ़ रहे ब्लैक फंगस इंफेक्शन के मामले : गुलेरिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश में ब्लैक फंगस को लेकर एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड मरीजों में हाल ही में फंगस इंफेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा सार्स के प्रसार के दौरान भी कुछ हद तक देखा गया था। गुलेरिया ने कहा कि कोविड के साथ अनियंत्रित डायबिटीज म्यूकरमाइकोसिस के पैदा होने में सहायक होता है। डॉ गुलेरिया ने कहा कि कोविड की इस लहर में स्टेरायड का इस्तेमाल कहीं अधिक हो गया है और हल्के और शुरूआती दौर में स्टेरायड दिए जाने से दूसरी तरह के इंफेक्शन हो सकते हैं। संकेत दिखे बिना जिन्हें स्टेरायड्स की हाई डोज दी जाती है उनमें हाई ब्लड शुगर और म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। एम्स निदेशक ने कहा कि हमें इस प्रसार पर लगाम लगाना ही होगा। इसके लिए तीन बातें बेहद जरूरी हैं- ब्लड शुगर लेवल को अच्छी तरह से काबू में रखा जाए, जिन लोगों को स्टेरायड्स दिए जा रहे हैं लगातार उनका ब्लड शुगर मॉनीटर किया जाना चाहिए, और जब स्टेरायड्स दी जाएं तो उनकी डोज को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए।

आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने वैक्सीन की कमी पर केंद्र से की अपील, निजी अस्पतालों को न दिया जाए टीका

अमरावती । देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टीकाकरण एक अहम अभियान है. अलग-अलग राज्यों के सामने वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर अपनी-अपनी समस्याएं हैं. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों की कोविड रोधी टीके की आपूर्ति रोकने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि टीके की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला आवश्यक है. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने निजी अस्पतालों पर टीके की खुराक के लिए लोगों से मनमानी कीमत वसूलने का आरोप भी लगाया.

रेड्डी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि निजी अस्पताल टीके की एक खुराक के लिए लोगों से 2,000-25,000 रुपये तक वसूल रहे हैं, जोकि दुनिया में उपलब्ध कोविड के टीके की सबसे महंगी खुराक में से एक है. उन्होंने कहा कि टीका आम जनता के हित के लिए है इसलिए नैतिक रूप से इसे निशुल्क अथवा एक तय कीमत में उपलब्ध कराया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि जब 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए ही टीके की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है और इस बात की भी कोई संभावना नहीं है कि अगले कुछ महीनों में 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू हो पाएगा, ऐसे में कुछ निजी अस्पतालों को मनमानी कीमत पर सभी आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने की अनुमति देना सही नहीं है.

जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि इसके कारण न सिर्फ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि इससे टीके की कालाबाजारी का खतरा भी बढ़ जाता है. उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में टीका लगवाने का विकल्प देना, उसी स्थिति में सही साबित होगा, जब टीके की खुराक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो. रेड्डी ने प्रधानमंत्री से इस मामले की ओर ध्यान देने का अनुरोध करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों को की जाने वाली टीके की आपूर्ति रोक दी जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में जहां वैक्सीन की आपूर्ति बहुत सीमित है. लोगों के पास निजी अस्पतालों का विकल्प है, लेकिन वो अत्याधिक कीमत वसूल करते हैं, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर गौर करें और प्राइवेट अस्पतालों को खत्म करें ताकि पूरा स्टॉक राज्य और केंद्र के पास उपलब्ध हो.

कार्टून

दुनिया के 48 देशों में फैला भारत में मिला कोरोना वैरिएंट

वाशिंगटन, (एजेंसी)। भारत में मिला कोरोना वायरस का बेहद संक्रामक स्ट्रेन बी1.617.2 अब दुनिया के 48 देशों में पहुंच गया है। आलम यह है कि अंटारकटिंका को छोड़कर विश्व के हर महाद्वीप में यह स्ट्रेन पहुंच गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमुख डॉक्टर जेनी हैरिस ने खुलासा किया कि तमाम यात्रा प्रतिबंधों के बाद भी भारत में मिला कोरोना वेरिएंट लगातार तेजी से फैल रहा है। यह पहले वायरस की तुलना में काफी ज्यादा संक्रामक है।

जेनेटिक सिक्वेंसिंग लाइब्रेरी से मिले डेटा से पता चला है कि भारत में मिला वेरिएंट यूरोप, नार्थ अमेरिका, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक पहुंच गया है। यह स्ट्रेन अब ब्रिटेन में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ब्रिटेन में इस वेरिएंट के 2,915 मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन, अमेरिका के अलावा जर्मनी, जापान और सिंगापुर भारत में मिले कोरोना वायरस के नए गढ़ बनकर उभर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीमा बंद करने के बाद भी वहां पर 74 मामले सामने आए हैं।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रफेसर जोनाथन वान टाम ने कहा कि भारत में मिला कोरोना स्ट्रेन ब्रिटेन के केंट स्ट्रेन की तुलना में 20 से 30 फीसदी ज्यादा संक्रामक है। इस बीच ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन प्रभावी हैं।

पाकिस्तान में फिलीस्तीन के समर्थन में रैली में विस्फोट, 7 की मौत, 13 घायल

इस्लामाबाद, (एजेंसी)। बलूचिस्तान प्रांत में फलस्तीन के समर्थन में एक रैली के दौरान हुए बम विस्फोट में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। सरकार के प्रवक्ता लियाकत शाहवानी ने कहा कि यह विस्फोट उस समय हुआ, जब रैली चमन शहर के एक बाजार से होकर गुजर रही थी। धमाके में छह लोगों की मौत हो गयी जबकि 14 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 10 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जबकि शेष लोगों को क्वेटा के अस्पतालों में भेजा गया है। घायलों में से तीन की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

यह रैली फलस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए निकाली जा रही थी। इस रैली में पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा करने की धमकी भी दी गयी। विस्फोट वाली जगह को सुरक्षाकर्मियों ने घेर दिया है। इस रैली का आयोजन इस्लामिक राजनीतिक संगठन जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-नजरयाती (जेयूआई-एन) ने किया था। रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल कादिर लुनी और कारी महरुल्ला भी मौजूद थे। दोनों नेता सुरक्षित हैं।

शाहवानी ने कहा, हमला करने वाले लोग फलस्तीन के प्रति एकजुटता के खिलाफ हैं और वे इजराइल का समर्थन करते हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह पता चला है कि रैली समाप्त होने से कुछ समय पहले ही एक धार्मिक नेता के वाहन को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट किया गया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री जाम कमाल खान ने इस हमले की निंदा की है।

इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है। गौरतलब है कि करीब एक महीने पहले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में सेरेना होटल की पार्किंग में एक धमाका हुआ था,जिसमें पांच लोगों की मौत हो गयी थी और 12 अन्य घायल हो गए थे। उसी होटल में चीन के राजदूत रुके हुए थे, लेकिन विस्फोट के समय वह होटल में मौजूद नहीं थे।

पाकिस्तान में हुए एक बम धमाके के बाद घटना स्थल पर मौजूद पुलिस। इस हादसे में छः लोगों के मारे जाने की खबर है।

इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष की समाप्ति की घोषणा के बाद जश्न मनाते फिलिस्तीन के नागरिक।

बोको हरम के लीडर अबू बकर शेकऊ ने खुद को विस्फोटक से उड़ाया

अबूजा, (एजेंसी)। कई साल से नाइजीरिया में आतंक मचाने वाले खूंखार संगठन बोको हरम के लीडर अबू बकर शेकऊ की मौत हो गई है। अधिकारियों का दावा है कि शेकऊ ने आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (आईएसडब्ल्यूएपी) से सामना होने पर शेकऊ ने विस्फोटकों से खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया। हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिहादी लड़ाकों के बीच हुई बातचीत के आधार पर यह दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बोको हरम और आईएसडब्ल्यूएपी के बीच उत्तरी नाइजीरिया के बोर्नो में झगड़ा हुआ, जहां हाल के दिनों में आईएसडब्ल्यूएपी काफी शक्तिशाली हो गया है। जर्नल ने लड़ाकों और उग्रवादी कमांडर के बीच हुई बातचीत के आधार पर दावा किया है कि शेकऊ ने बम डेटोनेट कर खुद को उड़ा दिया। नाइजीरिया की सेना के प्रवक्ता मोहम्मद येरिमी ने कहा है कि प्रशासन इस बारे में जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी खबरें आई हैं और वह वापस आ गया। वहीं, जर्नल से बातचीत में टोनी ब्लेयर इंस्टिट्यूट में एनालिस्ट बुलामा बुकार्ती ने कहा है कि शेकऊ दुनिया में सबसे ज्यादा लंब समय तक टिकने वाला आतंकी रहा है और दुनिया उसे काफी कम समझ पाई। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया के लिए यह अहम पल है। इस्लामिक संगठन- बोको हरम की स्थापना 2002 में मोहम्मद यूसुफ ने की थी।

स्थानीय भाषा- हौसा में बोको का मतलब पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना होता है, लेकिन 2009 में नाइजीरिया में एक इस्लामिक देश की स्थापना के लिए संगठन ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए। अमेरिका ने 2013 में बोको हरम को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। जब इसकी स्थापना की गई थी, तब यह अहिंसक था और इसका मुख्य उद्देश्य उत्तरी नाइजीरिया में इस्लाम को शुद्ध करना था। मार्च 2015 में यह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवंट (आईएसआईएल) से जुड़ गया। सन 2009 में शेकऊ के कमान संभालने के बाद से यह इतना हिंसक हो गया कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक एक वक्त पर सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक था।

नफतीर्ती का देवी की तरह होने लगा था सम्मान

काहिरा, (एजेंसी)। मिस्र के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के सामने प्राचीन फिरौन तूतनखामेन के बारे में जितनी पहेलियां सामने रही हैं, उनकी सौतेली मां रानी नफतीर्ती भी उतना ही बड़ा रहस्य बनी रही हैं। अब मिस्र विशेषज्ञ प्रफेसर एडेन डॉडसन ने कुछ नई जानकारियां शेयर की हैं। हिस्ट्रीएक्सट्रा पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है कि नफतीर्ती के बारे में और वह कहां से आईं, इसे लेकर कई भ्रांतियां हैं।

उनका कहना है, कुछ लोगों को लगता है कि वह एक राजकुमारी थीं। कुछ का कहना है कि वह कहीं बाहर से आई थीं। उनके नाम का मतलब है- एक खूबसूरत महिला आ गई है लेकिन उस काल में मिस्र में ऐसे नाम हुआ करते थे। एडेन का कहना है कि पिछले कुछ साल में नफतीर्ती के बारे में एक राजा की होने पत्नी से ज्यादा और भी कई बातें पता चली हैं। उन्होंने बताया है, अपने काल में नफतीर्ती मिस्र के दुश्मनों को भी आकर्षित करती थीं जो किसी और रानी में नहीं देखा गया। उनके संकेत अपने पति अखेनातेन के ताबूत पर भी मिलते हैं जबकि वहां आमतौर पर मृत्यु की देवियां होती हैं। उनका कहना है कि नफतीर्ती का देवी की तरह सम्मान होने लगा था। एडेन का दावा है कि नफतीर्ती आगे चलकर मिस्र की फिरौन भी बनीं, जो कम ही महिलाएं कर सकीं। हालांकि, उनका मकबरा अभी तक नहीं मिला है। बता दें कि मिस्र के प्राचीन फिरौन तूतनखामेन और उनकी सौतेली मां रानी नफतीर्ती से जुड़ा एक सबूत करीब 100 साल पहले मिला था और उसके बाद से रिसर्चर और जानकारी जुटाने की कोशिश में लगे रहे।

मां डायना की मौत के बाद टूट गए थे प्रिंस हैरी, शराब के सेवन की रहती थी तलब

लंदन, (एजेंसी)। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने 1997 में पेरिस में हुई कार दुर्घटना में अपनी मां प्रिंसेज डायना के निधन के बाद शराब की तलब, नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में सोचने और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से दो-चार होने के बारे में खुलकर बात की है। हैरी ने अमेरिकी टॉक शो की मेजबान ओप्रा विनफ्रे के साथ एप्पल टीवी के लिए बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आरोप लगाया कि जब उनकी पत्नी मेगन मर्केल सोशल मीडिया पर उत्पीड़न के बीच आत्महत्या के बारे में सोच रही थीं, तो ब्रिटेन के शाही परिवार ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था।

पिछले साल शाही परिवार को छोड़कर अमेरिका के कैलिफॉर्निया में बसने वाले हैरी (36) ने कहा, मैं पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि मेरा परिवार मदद करेगा, लेकिन हरेक सवाल, अनुरोध, चेतावनी आदि पर केवल चुप्पी साधी गई या पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, हमने चीजें पटरी पर लौटने की उम्मीद से चार साल गुजार दिए। हमने वहां साथ रहने के लिए जो कुछ संभव था, वह किया और अपना काम करते रहे। द मी यू कान्ट सी नामक इस सीरीज के लिए ओप्रा विनफ्रे से बात कहते हुए हैरी ने 28 से 32 साल के बीच के अपने जीवन को बुरा सपना करार दिया, जिसमें उन्होंने अवसाद और तनाव का सामना किया था। उन्होंने कहा, मैं मानसिक रूप से टूट चुका था। मुझे शराब पीने और नशीले पदार्थों के सेवन की तलब रहती थी। मुझे वह सब कुछ करने की तलब रहती थी, जिनसे मैं पहले की तरह हल्का महसूस कर सकूं। हैरी ने खुलासा किया कि वह सप्ताह में एक बार शुक्रवार या शनिवार की रात को शराब जरूर पीते थे। उन्होंने कहा कि वह आनंद के लिए नहीं बल्कि अपनी मां को खोने का दर्द भुलाने के लिये ऐसा करते थे।

बाइडेन की कोशिशों से थमा इजराइल-फिलीस्तीन का खूनी संघर्ष

वॉशिंगटन, (एजेंसी)। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों की जंग के बाद हुए संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संपर्क में रहे और उन पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बनाते रहे। संघर्ष विराम लागू होने से पहले नेतन्याहू ने बाइडेन को खुद फोन करके बताया था कि वह युद्ध समाप्त करने वाले हैं, इसके बावजूद बाइडेन चिंतित थे कि आखिरी वक्त में बात न बिगड़ जाए। व्हाइट हाउस के सहयोगियों ने इजरायल और मिस्र से यह पता लगाने के लिए फोन पर संपर्क किया कि संघर्ष विराम लागू होगा या नहीं। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और इजरायल के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमास की ओर से फिर से रॉकेट दागे जाने से मिस्र की मध्यस्थता में हुए समझौते पर पानी फिर सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की चिंता को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें फिर फोन करके भरोसा दिलाया कि सीजफायर होने वाला है। इसी के साथ बाइडेन के सामने राष्ट्रपति बनने के बाद आया पहला विदेश नीति संकट समाप्त हो गया। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस संकट को निपटाया। व्हाइट हाउस ने बताया कि इस दौरान बाइडेन और उनके वरिष्ठ सहयोगियों ने फोन के जरिए बात कर या व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर 80 बार संपर्क किए, ताकि युद्ध को विराम लग सके। संघर्ष विराम की खुशी में दिए गए अपने साढ़े तीन मिनट के भाषण में बाइडेन ने दोहराया कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने इजरायली बमबारी में मारे गए फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए शोक व्यक्त किया और वादा किया कि गाजा पट्टी के लिए मानवीय मदद मुहैया कराई जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि यदि अमेरिका द्वारा विकसित मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम नहीं होती तो मृतकों की संख्या और अधिक हो सकती थी। जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या अमेरिका की इजरायल नीति में कोई बदलाव आया है, तो उन्होंने कहा, इजरायल की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया है। हम केवल समस्या का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं और इसी के प्रयास किए गए। मैं फिर यही कहूंगा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है।

चीन में लगातार आए भूकंप के तेज झटके, तीन की मौत, 27 घायल

बीजिंग, (एजेंसी)। चीन में युन्नान प्रांत की यांग्बी यी स्वायत्त काउंटी में एक के बाद एक आए भूकंप में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के प्रांत के प्रमुख यांग गुओजोंग ने बताया कि दाली बाइ स्वायत्त प्रांत की सभी 12 काउंटी और शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए लेकिन यांग्बी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यांग्बी काउंटी में दो लोगों की और योंगपिंग काउंटी में एक व्यक्ति की मौत हुई। यहां की स्थानीय सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा 24 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। भूकंप से 20,192 मकानों में रह रहे करीब 72,317 निवासी प्रभावित हुए।

चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र (सीईएनसी) के अनुसार यांग्बी में शुक्रवार को रात नौ बजे से 11 बजे तक 5.0 तीव्रता से अधिक के चार भूकंप आए। इस क्षेत्र में देर रात दो बजे तक भूकंप के बाद के 166 झटके महसूस किए गए। बचाव दलों को भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है और बचाव अभियान चल रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिम चीन के किंगघई प्रांत में शनिवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

बीजिंग के समयानुसार शुक्रवार देर रात दो बजकर चार मिनट पर प्रांत में गोलोग तिब्बत स्वायत्त प्रांत की मादुओ काउंटी में भूकंप आया। मादुओ से 385 किलोमीटर दूर प्रांतीय राजधानी शहर शिनिंग के निवासियों ने भी भूकंप के झटके महसूस किए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अभी किसी के हताहत होने और मकान के ढहने की कोई खबर नहीं है। साथ ही बिजली तथा संचार सुविधाएं भी सामान्य हैं। हालांकि, भूकंप प्रभावित इलाके में राजमार्ग के कुछ हिस्से और पुल ढह गए हैं।

इटली की राजधानी रोम में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लेते इटली के प्रधानमंत्री मारियो और यूरोपियन कमीशन के राष्ट्रपति लियान।

अपनी ही गलतियों से बिगड़ रहे धरती के हालात : प्रो. लोएब

मैसाच्यूसेट्स, (एजेंसी)। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और प्रख्यात वैज्ञानिक एवी लोएब ने हाल ही में दुनिया के वैज्ञानिकों से सवाल किया कि दुनिया का अस्तित्व कब तक कायम रहेगा और इंसानों की कौम कब तक अपना अस्तित्व कायम रखेगी उन्होंने कहा कि धरती के खत्म होने या इंसानों के खत्म होने की तारीख क्या होगी, क्योंकि उन्हें लगता है साइंटिस्ट सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। एवी लोएब ने वैज्ञानिकों से अपील की है कि अगर दुनिया और प्राणियों का अस्तित्व जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाएं, सतत ऊर्जा के विकल्प खोजें, सबको खाना मिले इसका तरीका निकाले, अंतरिक्ष में बड़े बेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर लें। साथ ही एलियंस से संपर्क करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस दिन हम तकनीकी रूप से पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे, उस दिन इंसानों की पूरी पीढ़ी और धरती नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय यही सारी खोज और तकनीकी विकास कुछ इंसानों को बचा पाएंगी।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सम्मेलन में संबोधित करते हुए एवी लोएब ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है इंसानों की उम्र को बढ़ाना। क्योंकि मुझसे पूछा जाता है कि हमारी तकनीकी सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रहेगी। मेरा जवाब है कि हम लोग अपने जीवन के मध्य हिस्से में हैं। हमारी तकनीकी सभ्यता की शुरूआत सैकड़ों साल पहले हुई थी। तब यह बच्चा था। अभी हम इसके किशोरावस्था को देख रहे हैं। यह लाखों साल तक बची रह सकती है। हम फिलहाल अपने टेक्नोलॉजिकल जीवन का युवापन देख रहे हैं। यह कुछ सदियों तक जीवित रह सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं। यह एक गणितीय गणना के आधार पर एवी लोएब ने बताया।

लेकिन क्या यह भविष्य बदला जा सकता है एवी लोएब ने कहा कि जिस तरह से धरती की हालत इंसानों की वजह से खराब हो रही है, उससे लगता है कि इंसान ज्यादा दिन धरती पर रह नहीं पाएंगे। कुछ सदियों में धरती की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा तकनीकी आपदा का है। ये तकनीकी आपदा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी होगी। इसके अलावा दो बड़े खतरे हैं इंसानों द्वारा विकसित महामारी और देशों के बीच युद्ध। इन सबको लेकर सकारात्मक रूप से काम नहीं किया गया तो इंसानों को धरती खुद खत्म कर देगी। या फिर वह अपने आप को नष्ट कर देगी। ये भी हो सकता है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती पर इतना अत्याचार हो कि वह खुद ही नष्ट होने लगे।

एवी लोएब ने कहा कि इंसान उन खतरों से खुद को नहीं बचा पाते जिससे वे पहले कभी न टकराए हों। जलवायु परिवर्तन की वजह से अलग-अलग देशों में मौसम बदल रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है। सैकड़ों सालों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से आग उगलने लगे हैं। जंगल आग से खाक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आग कैसे कोई भूल सकता है। करोड़ों जीव मारे गए उसमें। फिजिक्स का साधारण मॉडल कहता है कि हम सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी मूल तत्वों से बने हैं। इनमें अलग से कुछ नहीं जोड़ा गया है। इसलिए प्रकृति के नियमों के आधार पर हमें मौलिक स्तर पर इनसे छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि सभी मूल तत्व फिजिक्स के नियमों के तहत आपस में संबंध बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर इनसे छेड़छाड़ की आजादी मिलती है तो इससे नुकसान ही होगा।

केंद्र से वैक्सीन मिलने पर सभी सेंटर चालू हो जाएंगे : केजरीवाल

नई दिल्ली (आनंद राय) । सीएम अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि मुझे बेहद दुख है कि हमें वैक्सीन खत्म होने के कारण कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र सरकार को भी लिख कर बताया है। हमने केंद्र सरकार से और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी, हम फिर से यह सेंटर शुरू कर देंगे। दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की डोज की जरूरत है। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन की डोज मिली। वहीं, जून के महीने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोठा और भी कम कर दिया है। केंद्र सरकार से हमें जो चिट्ठी आई है, उसके मुताबिक, जून में दिल्ली को केवल 8 लाख वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जबकि मई महीने में 16 लाख वैक्सीन की डोज दी गई थी। सीएम ने कहा कि अभी तक हम दिल्ली में कुल 50 लाख वैक्सीन की डोज लगा चुके हैं और दिल्ली के सभी वयस्क को वैक्सीन लगाने के लिए हमें ढाई करोड़ और वैक्सीन की डोज चाहिए। अगर हम इसी रफ्तार से चले और दिल्ली को हर महीने 8 लाख वैक्सीन मिली तो, दिल्ली के वयस्क लोगों को वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे। बल्कि इससे भी ज्यादा महीने लग जाएंगे। तब तक तो न जाने कितनी कोरोना की लहरें आएंगे और न जाने कितनी और लोगों की मौतें हो जाएगी। तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन की सुरक्षा दी जाए। बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन और दवाई आदि इन सब की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के घातक असर से बचाने में वैक्सीन ही सबसे ज्यादा असरदार हथियार है।

सीएम ने कहा कि वैक्सीन की कमी केवल सरकार की चिंता नहीं है, बल्कि आम आदमी भी वैक्सीन के संकट से बहुत डरा हुआ है। कल एक अम्मा का फोन आया। वह बोली कि मुझे और मेरे बेटे को वैक्सीन लगवानी है। मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों की कितनी उम्र है। अम्मा ने बताया कि मेरी उम्र 65 साल है और मेरे बेटे की उम्र 35 साल है। मैंने कहा कि युवाओं की वैक्सीन तो खत्म हो गई है, लेकिन आपको लगवा दूंगा। थोड़ा सोच कर उन्होंने बोला कि मेरी वाली वैक्सीन मेरे बेटे को लगवा दें। बेटा नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूं। उसे तो आगे परिवार भी संभालना है। इसलिए उसका सुरक्षित रहना जरूरी है। यह सुनकर दिल में बहुत पीड़ा हुई। आज वैक्सीन की कमी की वजह से देश में बेहद मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। अगर देश में किसी पिता, किसी बेटे, किसी भाई किसी मां, किसी बहन के सामने यह धर्म संकट है कि वह खुद वैक्सीन ले या अपने परिवार के युवाओं के लिए छोड़ दें, तो इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कोरोना वारियर्स को बांटने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को खाद्य सामाग्री भेंट की।

डीटीसी के 30 से अधिक कर्मियों की कोरोना से मौत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना काल के दौरान सार्वजनिक परिवहन, ऑक्सीजन सिलिंडर की आपूर्ति सहित जरूरी कार्यों को अंजाम देने वाले दिल्ली परिवहन निगम(डीटीसी) के 30 से अधिक कर्मियों की पिछले दिनों कोरोना से मौत हो चुकी है। इनमें परिचालक, चालकों सहित सभी वर्ग के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। कोरोना काल के शुरूआती दौर से डीटीसी की बसों में लोगों को क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाया गया तो अनलॉक के दौरान गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचाने और ऑक्सीजन की आपूर्ति में डीटीसी कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई। पिछले करीब डेढ़ महीने के दौरान प्रबंध निदेशक के ओएसडी, क्षेत्रीय प्रबंधक, उप मुख्य महाप्रबंधक सहित अलग अलग वर्गों के कर्मचारी कोरोना से जान गंवा चुके हैं। डिपो की बसों में तेनात चालक और परिचालक सहित निगम के दफ्तरों में तैनात कर्मियों की भी कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। डीटीसी के मुताबिक ड्यूटी के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। फिर भी फील्ड ड्यूटी में तैनात कर्मी कोरोना की चपेट में अधिक आए हैं।

शरजील उस्मानी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शरजील उस्मानी के कथित आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भाजपा के एक नेता की शिकायत के आधार पर शरजील उस्मानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले 20 मई को महाराष्ट्र के जालना जिले में भी पुलिस ने पूर्व छात्र नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की थी। कार्यकर्ता और जालना के अंबाद में रहने वाले शिकायतकर्ता अंबादास अंभोरे ने आरोप लगाया था कि शरजील उस्मानी ने ट्विटर पर अपने कुछ हालिया पोस्ट में भगवान राम के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और धार्मिक भावनाओं को आहत किया।

एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार को दिए ये आदेश

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और जरूरी उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजारी करना अब आसान नहीं होगा। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने कई अहम फैसले लिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीएमए के अध्यक्ष अनिल बैजल ने शनिवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि लोगों को कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के इलाज से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि डीलरों या विक्रेताओं द्वारा ऐसी दवाइयों पर ज्यादा दाम नहीं लिए जाएं तथा इनकी कालाबाजारी न हो सके। उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि कोविड-19 से संबंधित उपकरणों और मशीनों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आदि के संबंध में एक समान आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके साथ ही डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में कोरोना के इलाज से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी अधिकृत डीलर, खुदरा विक्रेता और विक्रेता आम जनता के लिए अपने व्यावसायिक परिसरों में विशिष्ट स्थानों पर दवाओं के स्टॉक और उनके दाम की जानकारी प्रदर्शित करेंगे। स्टॉक की स्थिति दिन में चार बार सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे अपडेट करनी होगी। दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 2260 नए मामले सामने आए तथा 182 लोगों की मौत हो गई। वहीं, अब संक्रमण दर 3.58 प्रतिशत पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च के बाद से सबसे कम मामले आए हैं और एक अप्रैल के बाद से संक्रमितों की संख्या 3000 के नीचे रही। दिल्ली में 31 मार्च को 1819 और एक अप्रैल को 2790 मामले आए थे। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली में मृतकों की संख्या 23,013 हो गई है। संक्रमण दर गुरुवार को 5.5 प्रतिशत थी और शुक्रवार को 4.76 प्रतिशत हो गई। एक्टिव मामलों की संख्या 31,308 है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर कहा कि संक्रमण के 2260 नए मामले आए हैं। उन्होंने कहा, 31 मार्च के बाद से ये सबसे कम संख्या है। अब भी तमाम सावधानी और कोविड के संबंध में उचित व्यवहार अपनाने की जरूरत है।

एडीएम का फर्जी पास बनाकर शादी की बुकिंग लेते थे दो सगे भाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लॉकडाउन के दौरान एडीएम नॉर्थ नितिन जिंदल के हस्ताक्षर वाले नकली पास बनाने के आरोप में कापसहेड़ा थाना पुलिस ने दो सगे भाईयों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में भारत, दीपक और हेमंत शामिल है।

नकली पास भारत ने बनाया था और बाकि दोनों आरोपी उसका इस्तेमाल किया था। भारत और दीपक सगे भाई हैं। जबकि हेमंत पेशे से वकील है। पुलिस उपायुक्त इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि 16 मई को एडीएम नॉर्थ नितिन जिंदल की ओर से एक शिकायत मिली थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि वह कापसहेड़ा में बतौर एसडीएम तैनात थे। कुछ लोग एसडीएम कापसहेड़ा के हस्ताक्षर वाले नकली पास लेकर घूम रहे हैं।

इस पास पर नितिन जिंदल के हस्ताक्षर और मुहर लगी हुई है। उनकी शिकायत पर कापसहेड़ा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर एसआई विवेक कुमार की टीम को जांच सौंपी। जांच के दौरान पुलिस को दीपक के बारे में पता चला और पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसने पूछताछ में बताया कि वह बैंड की दुकान चलाता है और इस फर्जी पास को दिखाकर वह शादियों में बैंड-बाजे की बुकिंग ले लेता था। इस काम में उसका भाई हेमंत मदद करता था और यह पास भारत ने उसे दिया था। पुलिस ने बाकी दोनों आरोपियों को भी दबोच लिया।

राशन के मुफ्त वितरण की समीक्षा के लिए इमरान हुसैन ने की उच्च स्तरीय बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री, इमरान हुसैन ने दिल्ली में एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा के लिए खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) के सीएमडी और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और डीएससीएससी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी राशन की दुकानें (एफपीएस) बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के प्रतिदिन नियमित रूप से खुलें। उन्होंने अधिकारियों को राशन के सुचारू और आसान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए और कहा कि लाभार्थियों को राशन दुकान से राशन प्राप्त करने में किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। इमरान हुसैन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एफपीएस डीलर एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई दोनों के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन की मात्रा , स्टॉक की स्थिति, लाभार्थियों की कुल संख्या से संबंधित जानकारी और अन्य निर्धारित जानकारी फ्लेक्स बोर्ड, बैनर आदि पर एफपीएस के बाहर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। उन्होंने अधिकारियों को बिना किसी देरी के लाभार्थियों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सीएफएस को एक बार फिर एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए मुफ्त राशन वितरण से संबंधित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।

इमरान हुसैन ने लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और राशन प्राप्त करने के लिए किसी भी लाभार्थी को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया की सभी राशन डीलरों को एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत पूरा राशन एक बार में देने का निर्देश दिया गया है। लेकिन किसी कारणवश , यदि लाभार्थी पूरा राशन एक बार में नहीं प्राप्त कर पातें है तो शेष राशन प्राप्त करने के लिए वे फिर से एफपीएस पर जा सकते हैं। एफपीएस डीलर उन्हें शेष राशन का वितरण सुनिश्चित करेंगे। खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने दोहराया कि राशन दुकानें (एफपीएस) सभी सातों दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के खुली रहेंगी। निदेशों का पालन न करने पर दोषी एफपीएस डीलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि वैसे सभी राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो नियमित रूप से दुकानें नहीं खोलते हैं या जो निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित करते हैं या जमाखोरी, कालाबाजारी, लाभार्थियों के साथ दुर्व्यवहार आदि कदाचार में लिप्त हैं।

दिल्ली सरकार छोटे बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दे रही है : राजेंद्रपाल गौतम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत दिए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता और मात्रा की जांचने के लिए विश्वास नगर की युधिष्ठिर गली और त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 10 और 11 में घर-घर जाकर निरीक्षण किया। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लॉकडाउन के दौरान पहले भी पोषण आहार की जांच के लिए कई इलाकों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं।

कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम ने इन इलाकों में घर-घर जाकर आईसीडीएस के तहत मिल रहे पोषण आहार की मात्रा और गुणवत्ता की जांच पड़ताल की। इन इलाकों में रह रहे लाभार्थियों से बात की और पूछा कि इस योजना के तहत उन्हें क्या-क्या मिल रहा है और उसकी गुणवत्ता कैसी है श्री गौतम ने कहा कि यदि उन्हें तय मानक के अनुसार आहार नही दिया जा रहा है या गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है, तो लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस योजना के तहत, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं और बच्चों को आईसीडीएस के तहत राशन मिलता हैं। योजना के तहत, 1300 ग्राम दलिया, 260 ग्राम काले चने (कच्चे), 130 ग्राम गुड़ और 130 ग्राम भुने काले चने की मात्रा बच्चों को 13 दिनों के लिए वितरित किया जाता है। स्तनपान करा रही और गर्भवती महिलाओं के लिए 1690 ग्राम दलिया, 260 ग्राम काले चने (कच्चे), 130 ग्राम गुड़ और 130 ग्राम भुने काले चने का वितरण किया जाता है।

ब्लैक फंगस को जल्द महामारी घोषित करे सरकार :भाजपा

नई दिल्ली । भाजपा ने दिल्ली सरकार से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की मांग की है। उसका कहना है कि सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। यदि समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति गंभीर हो सकती है। पार्टी ने सरकार से अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है जिससे कि इस चुनौती से निपटने के लिए तैयारी तेज हो सके।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि आठ राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। दिल्ली में इसके दो सौ से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं लेकिन, सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी इसे महामारी घोषित करके इसे रोकने के लिए तैयारी शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ के डाक्टरों के अनुसार कोरोना मरीज के इलाज में लापरवाही से यह समस्या हो रही है, इसलिए अस्पतालों के औचक निरीक्षण करने की जरूरत है।

दिल्ली में कोरोना का खत्म हुआ कहर 2260 नए केस 6453 मरीज हुए ठीक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब तेजी से कम हो रहा है। नए मामलों में भी कमी लगातार जारी है। दिल्ली में शनिवार को जहां संक्रमितों की संख्या घटकर 2200 पर आ गई, वहीं अब संक्रमण दर भी घटकर 3 फीसदी पर पहुंच गई है। राहत की बात यह भी है कि आज मृतकों की संख्या 200 से कम रही। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 2260 नए मरीज मिले हैं, वहीं 182 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब संक्रमण दर घटकर 3.58 प्रतिशत पर आ गई है, जो शुक्रवार को 4.76 थी। बुलेटिन के अनुसार, आज 6,453 मरीज पूरी तरह ठीक होकर कोरोना मुक्त हो गए, जबकि शुक्रवार को यह संख्या 7,288 थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 14,15,219 हो गई है और 18,060 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस घटकर 31,308 पर आ गए हैं। इसके साथ ही, अब तक कुल 13,60,898 मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल मृतकों का आंकड़ा 23,013 पर पहुंच गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब काफी कम हो गई है। संक्रमण दर भी घटकर 3.5% रह गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना का खतरा अब टल गया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज से 18 साल से ऊपर के युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितनी वैक्सीन भेजी थीं वो खत्म हो गई हैं। कुछ वैक्सीन की डोज बची हैं वो कुछ सेंटर में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक खत्म हो जाएंगी। दिल्ली में रविवार से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे।

गंगाराम अस्पताल में मिले बीमारी के दो दुर्लभ केस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना महामारी के बीच देशभर के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस के इन मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं, इस बीमारी के कई ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान होने लगे हैं। सरकार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार, कोविड महामारी के अलावा ब्लैक फंगस के मामलों की बढ़ती चिंता के बीच, दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में छोटी आंत के म्यूकोरमाइकोसिस के दुर्लभ मामले सामने आए हैं। 56 वर्षीय दिल्ली निवासी कुमार ने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य दो सदस्यों को कोविड के कारण खो दिया है। पेट में दर्द होने के बावजूद उन्होंने बमुश्किल अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। पत्नी के साथ उन्हें भी कोरोना हुआ था और शुरू में उनमें हल्के लक्षण थे। उनके पेट के दर्द को गैस्ट्राइटिस/तनाव से संबंधित माना गया और खुद ही एसिडिटी दवा ले ली, जिससे उचित इलाज में तीन दिन की देरी हुई। अंततः सर गंगा राम अस्पताल की कोविड इमरजेंसी में उनकी जांच की गई। सीटी स्कैन से पता चला कि उसकी छोटी आंत जेजुनम में छेद हो गया था। वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता के कारण उनकी कोविड बीमारी भी अब गंभीर हो गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार, संक्रमितों द्वारा बिना डॉक्टरों की सलाह के घर में स्टेरॉयड का अनावश्यक अधिक इस्तेमाल करने की वजह से इस तरह के मामले आ रहे हैं। यह फंगल संक्रमण फेफड़ों, साइनस, आंखों और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है तथा डायबिटीज के मरीजों के लिए घातक हो सकता है।

ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के एलएनजेपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पतालों में विशेष सेंटर बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध किया जाएगा और बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के एमडी डॉ. सुरेश कुमार ने शनिवार को बताया कि हमारे यहां कल ब्लैक फंगस के 13 मरीज थे और आज 21 मरीज हो गए हैं। दिल्ली के बाहर से ज्यादा लोग आ रहे हैं, हमारे पास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से मामले आ रहे हैं। दिल्ली एम्स में न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. पी शरत चंद्रा ने बताया कि फंगल इंफेक्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह महामारी जितना कभी नहीं हुआ है।

हम इसका सटीक कारण तो नहीं जानते हैं कि यह महामारी के अनुपात में क्यों पहुंच रहा है, लेकिन हमारे पास यह मानने का कारण है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अनियंत्रित डायबिटीज, टोसिलिजुमैब के साथ स्टेरॉयड का उपयोग, वेंटिलेशन पर रोगी का ऑक्सीजन लेना है। यदि इनमें से कोई भी कारण है तो कोरोना के इलाज के 6 सप्ताह के भीतर लोगों को ब्लैक फंगस का सबसे अधिक खतरा होता है। डॉ. चंद्रा ने कहा कि सिलेंडर से सीधे ठंडी ऑक्सीजन देना बेहद खतरनाक है। 2-3 सप्ताह तक मास्क का उपयोग करना ब्लैक फंगस के विकास का एक कारण हो सकता है। ब्लैक फंगस की घटनाओं को कम करने के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को एंटी-फंगल दवा पॉसकोनाजोल दी जा सकती है।

संपादकीय

दक्षिण में नए मुख्यमंत्रियों की चुनौती

केरल और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्रियों के लिए मानो आसमान से गिरे खजूर पर लटके जैसी स्थिति हो गई है। दोनों मुख्यमंत्री (केरल के पी विजयन और तमिलनाडु के एम के स्टालिन) एक मुश्किल चुनाव से गुजरकर आए हैं, लेकिन अपनी जीत का वे एक मिनट भी जश्न नहीं मना सके, क्योंकि उन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा, जो कहीं अधिक कठिन हो चली है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सादे समारोहों में पद की शपथ ली और लॉकडाउन की घोषणा करते हुए अपने कामकाज में जुट गए। चूंकि अगले हफ्ते दिल्ली सहित देश के उत्तरी हिस्से में इस महामारी के चरम पर पहुंचने की आशंका है, इसलिए दोनों मुख्यमंत्रियों को पता है कि कुछ हफ्तों के बाद दक्षिणी राज्यों की बारी भी आ सकती है। दरअसल, पिछले साल तमिलनाडु और केरल में महामारी की चरम स्थिति देश के उत्तरी हिस्सों में कोरोना के शीर्ष पर पहुंचने के दो हफ्ते बाद आई थी। इसीलिए महामारी विशेषज्ञ इस बार भी कुछ ऐसा ही अंदेशा जता रहे हैं और संक्रमण को थामने के लिए कठोर कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं। यही कारण है कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने सत्ता संभालते ही सबसे पहला काम लॉकडाउन लगाने का किया। इसका मकसद जाहिर तौर पर बीमारी की चरम स्थिति को कुछ समय के लिए टालना है, ताकि अस्पतालों के दबाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। दोनों राज्यों में संक्रमण और मौतें पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। केरल में रविवार को पॉजिटिविटी रेट (जांच की गई कुल संख्या में संक्रमित मरीजों का प्रतिशत) 28.88 फीसदी थी, जबकि तमिलनाडु में 15 प्रतिशत से अधिक। दोनों राज्यों में इस स्थिति की कल्पना नहीं की गई थी। बेशक, अन्य प्रदेशों की तुलना में यहां की स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बेहतर है, लेकिन अभी संकट इतना गहरा है कि वे उसे भी झुला रहा है। हाल के चुनावों में दोनों राज्य शारीरिक दूरी के पालन को लेकर भी निश्चिंत से दिखने लगे थे। पी विजयन तो अपनी वही लड़ाई जारी रखेंगे, जो वह पिछले एक साल से लड़ रहे हैं। उनके पांच साल के पिछले कार्यकाल में दो चक्रवाती तूफान आए थे और दो चिकित्सा आपदा। सबसे पहले निपाह वायरस आया था, जिसे केरल ने बढ़िया से संभाल लिया, लेकिन अब कोरोना वायरस उसे भी हलकान कर रहा है। चूंकि संक्रामक बीमारियों से लड़ने का केरल का अपना अनुभव है, इसलिए जब 31 जनवरी, 2020 को यहां देश के पहले तीन कोरोना मामले सामने आए, तब इसने शानदार तरीके से काम शुरू किया। इसने संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उन्हें एकांतवास में रखने और शारीरिक दूरी जैसे उपाय अपनाए, जो उस वक्त शेष भारत के लिए अनसुने थे। मगर यह सूबा दूसरी लहर से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री अपनी दैनिक प्रेस-वार्ता में आश्वस्त दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिलों में संक्रमण काफी अधिक है। एर्णाकुलम, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम के प्रभावित जिलों में तो ऑक्सीजन बेड शत-प्रतिशत भर चुके हैं। केरल में उत्तरी राज्यों जैसे हालात बन रहे हैं, जो वाकई चिंतनीय है। जैसे, पठानमथिट्टा जिले में एक 38 वर्षीय युवक और त्रिशूर में 66 वर्षीया महिला की इसलिए मौत हो गई, क्योंकि उन्हें आईसीयू बेड नहीं मिल सका। इससे पूरे राज्य में खतरे की घंटी बज गई है। इसी तरह, राज्य के शवदाह-गृहों पर भी दबाव बढ़ गया है। बेशक यहां बुनियादी ढांचा मौजूद है, लेकिन वह समान रूप से सभी जगह पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में, अब उन सभी जगहों पर फौरन बुनियादी ढांचा खड़ा करने की चुनौती है, जहां संक्रमण फैल रहा है। इसी के साथ ऑक्सीजन बेड को भी बढ़ाने की दरकार है। रही बात तमिलनाडु की, तो दशकों से मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले स्टालिन सावधानी से अपने कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि शुरुआती 100 दिनों का प्रदर्शन और महामारी के प्रबंधन के उनके प्रयासों के आधार पर ही उनके कार्यकाल को सफल या विफल बताया जाएगा। काडर आधारित पार्टी होने के कारण द्रमुक की अपनी समस्याएं हैं। समाज के एक तबके में पार्टी की छवि अच्छी नहीं है और यह माना जाता है कि जब यह सत्ता में आती है, तब राज्य में 'गुंडागर्दी' को हवा मिलती है। स्टालिन इस धारणा से परिचित हैं और इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन द्रमुक को चुनावी जीत मिली थी, उसी दिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था और अम्मा कैंटीन को निशाना बनाया था, जिनमें रियायती दरों पर लोगों को खाना मिलता है। ये कैंटीन दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की देन हैं, जो गरीबों में खासा लोकप्रिय है। महामारी के दौरान भी कई लोग इन कैंटीन पर निर्भर हैं। लिहाजा, जब स्टालिन को इन घटनाओं का पता चला, तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने न सिर्फ निशाना बनाए गए कैंटीन को दुरुस्त करवाया, बल्कि इन घटनाओं में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। स्टालिन ऐसे किसी कदम से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यह संदेश जाए कि वह बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके विरोधियों को मदद मिलेगी। फिर, वह उन अधिकारियों को लेकर भी संजीदा हैं, जो महामारी से निपटने में अच्छा काम कर रहे हैं। बेशक उन्होंने चेन्नई नगर निगम के प्रभारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया है, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को नहीं बदला है, जो महामारी के कुशल प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने सचिवालय में भी चर्चित और कुशल अधिकारी नियुक्त किए हैं। अपने कार्यकर्ताओं को लिखे पहले खत में उन्होंने स्वच्छ और कुशल प्रशासन का वादा किया है। बहरहाल, स्टालिन एक सजग राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। शायद यही कारण है कि वह अन्नाद्रमुक के पिछले शासन को विफल करने के प्रयास से बच रहे हैं। विधानसभा के अंदर एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने और अन्नाद्रमुक शासन के खिलाफ जनमत बनाने के बजाय उन्होंने अदालत में जाने का रास्ता चुना है। द्रमुक काडरों के बीच यह चर्चा थी कि यदि उनके पिता एम के करुणानिधि जीवित होते, तो उन्हें कहीं आसानी से सत्ता मिल जाती। स्टालिन इन सबको नजरंदाज करते हुए अपना एक अलग राजनीतिक रास्ता बना रहे हैं।

प्रवीण कुमार सिंह

विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ का खेल खतरनाक स्तर पर पहुंचा, अब भुगत रहे अंजाम

आज हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, ये दौर भी निकल जाएगा। हम इस महामारी के प्रकोप से उबर भी जाएंगे लेकिन प्रकृति को जो नुकसान हमने पहुंचा दिया है उसको जल्द पाटना मुश्किल होगा। कोरोना की महामारी ने हमें एक बार इस बात की याद दिलाई है कि हम भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौटें, हमारी जो परंपरा रही है, हमारे पूर्वजों ने जो विधियां अपनाई थीं, उसको अपनाएं। हम पेड़ों से फिर से रागात्मक संबंध स्थापित करें, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

आज पूरे देश के शहरी इलाकों में ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम है। अदालतें ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सरकार पर सख्ती बरत रही हैं, सरकारें ऑक्सीजन के उत्पादन और वितरण में रात दिन लगी हुई हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन के संयत्र लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन वितरण के लिए विदेशों से टैंकर मंगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के छोटे सिलिंडरों की कालाबाजारी हो रही हैं। विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मगंवाए जा रहे हैं। समाजसेवी संस्थाएं और सक्षम लोग इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण कर रहे हैं।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना जैसी महामारी से निबटने के लिए ऑक्सीजन बेहद आवश्यक है। है भी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमने प्रकृति के साथ अबतक क्या किया और अब इन कंसंट्रेटर के माध्यम से क्या करने जा रहे हैं। क्या हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा पर इन कंसंट्रेटर का असर नहीं पड़ेगा? गर्मी के बढ़ने के साथ एरकंडीशनर का उपयोग बढ़ेगा और कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी होगी। याद करिए अमेरिका में कोरोना की पहली लहर का कितना भयानक असर हुआ था और उसने कैसी तबाही मचाई थी। वो तब था जब अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक विकसित देश है और वहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं।

दरअसल हम तथाकथित आधुनिकता की अंधी दौड़ में इस कदर शामिल हो गए कि अपने भारतीय मूल्यों को लगातार बिसरते चले गए। हमारे देश में प्रकृति को लेकर एक अनुराग प्राचीन काल से रहा है। प्रकृति और पेड़ों को तो हमारे यहां भगवान मानकर पूजने की परंपरा रही है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में वृक्षों और पौधों को लेकर कई तरह की मान्यताओं की बात कही गई है। पीपल, वट, तुलसी आदि की तो पूजा तक की जाती रही है। इन वृक्षों और पौधों को लेकर लोक में

जो मान्यता है वो उनको धर्म से भी जोड़ती हैं। महाभारत के आदिपर्व में एक श्लोक में घने वृक्षों की महिमा का वर्णन है। कहा गया है कि किसी भी गांव में घुसते ही जब आपको कोई वृक्ष दिखाई देता है जो पत्तों से छतनार हो और फलों से लदा हुआ हो तो वो अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण प्रसिद्ध होता है। आसपास के लोग उस वृक्ष की पूजा करते हैं। वैदिक साहित्य में भी वृक्ष की महिमा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी वृक्षों की पूजा की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। यह अनायास नहीं है कि बुद्ध और तीर्थंकर के नाम के साथ एक पवित्र वृक्ष भी जुड़ा हुआ है जिसे बोधिवृक्ष कहते हैं। हिंदू धर्म में भी कल्पवृक्ष की मान्यता है जो लोक में व्याप्त है।

मान्यता ये है कि देवता और असुरों के समुद्र मंथन के समय ही कल्पवृक्ष का जन्म हुआ जिसको स्वर्ग में इंद्र देवता के नंदनवन में लगा दिया गया। लोक में इस कल्पवृक्ष की मान्यता के अलावा इसका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। उन ग्रंथों में इस वृक्ष को उत्तरकुरू देश का वृक्ष माना गया है। महाभारत में भी उत्तरकुरु देश में सिद्ध पुरुषों के रहने का वर्णन मिलता है और उस वर्णन के दौरान ऐसे वृक्ष का उल्लेख मिलता है जो हमेशा फलता फूलता रहता है। हमेशा हरा भरा रहता है। कुछ इसी तरह का वर्णन रामायण में भी मिलता है। सुग्रीव जब सीता को खोजने के लिए अपनी वानर सेना को उत्तर दिशा की ओर भेज रहा होता है तब वो अपनी सेना से कहते हैं कि इस दिशा के अंत में उत्तरकुरु प्रदेश है। उस प्रदेश की पहचान ये है कि वहां वहां वैसे वृक्ष मिलेंगे जो सदा फलते-फूलते रहते हैं। उन वृक्षों से ही उस प्रदेश की पहचान है।

इसके अलावा भी अगर हम अपनी परंपराओं पर विचार करें तो हमारे यहां उद्यानों की बहुत पुरानी परंपरा दिखाई देती है। आज जिसे किचन गार्डन कहकर महिमा मंडित किया जाता है उसकी जड़े हमारे पौराणिक समय में ही देखी जा सकती हैं। काव्यादर्श में तो स्पष्ट कहा गया है कि 'महाकाव्य का स्वरूप तबतक पूरा नहीं समझा जा सकता है जबतक उसमें उद्यान क्रीड़ा या सलिल क्रीडा का वर्णन न हो।' मुगल काल में भी इसी परंपरा को बढ़ाते हुए गृह-उद्यान की परंपरा को अपनाया गया और उसको नजरबाग कहा गया। शासकों और राजाओं के उद्यान लीला का वर्णन साहित्यिक रचनाओं में भी मिलता है। उन उद्यानों में पेड़ों की कतार और उसके बीच छोटे छोटे तालाब या जलकुंड का उल्लेख मिलता है। धर्म से लेकर लोक तक में प्रकृति के साथ जो संबंध थे वो कालांतर में बाधित होते चले गए। जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ा।

आधुनिकता और शहरीकरण के अंधानुकरण के दबाव में हमने खुद को प्रकृति के दूर करना आरंभ किया। विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ का खेल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पेड़ों की जगह गगनचुंबी इमारतों ने ले ली। हाइवे और फ्लाइओवर के चक्कर में हजारों पेड़ काटे गए। ये ठीक है कि विकास होगा तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेंगी लेकिन विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना भी तो हमारा ही काम है।

अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो क्या उस अनुपात में पेड़ लगा रहे हैं। हमने नीम, पीपल और बरगद के पेड़ हटाकर फैशनेबल पेड़ लगाने आरंभ कर दिए थे, बगैर ये सोचे समझे कि इसका पर्यावरण और प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा। आज जब ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है तो हमें फिर से नीम और पीपल के पेड़ों की याद आ रही है। आज मरीज की जान बचाने के लिए कंसंट्रेटर का उपयोग जरूरी है पर उतना ही जरूरी है उसके उपयोग को लेकर एक संतुलित नीति बनाने की भी।

आज हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, ये दौर भी निकल जाएगा। हम इस महामारी के प्रकोप से उबर भी जाएंगे लेकिन प्रकृति को जो नुकसान हमने पहुंचा दिया है उसको जल्द पाटना मुश्किल होगा। कोरोना की महामारी ने हमें एक बार इस बात की याद दिलाई है कि हम भारत के लोग अपनी जड़ों की ओर लौटें, हमारी जो परंपरा रही है, हमारे पूर्वजों ने जो विधियां अपनाई थीं, उसको अपनाएं। हम पेड़ों से फिर से रागात्मक संबंध स्थापित करें, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

महामारी के समय लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्यों की अधिक जिम्मेदारी

कोविड-19 महामारी ने उन कमियों को उजागर किया है, जो भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में व्याप्त हैं। कई मसलों पर केंद्र और राज्यों के बीच असहमति पैदा हो जा रही है। महामारी को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग एक गंभीर आवश्यकता है और भारत में इसकी अनुपस्थिति एक बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्णतः केंद्र का विषय हो या राज्य का, देश में इस पर बहस शुरू हो गई है। संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची के अनुसार जन स्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल एवं औषधालय राज्यों के अधिकार में आते हैं। इस कारण महामारी के समय लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें महामारी से बचाने की जिम्मेदारी राज्यों की अधिक हो जाती है। हालांकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कुछ कार्यक्रम जैसे चिकित्सा शिक्षा, परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समग्र रूप से देखें तो देश में जन स्वास्थ्य कुछ मायनों में केंद्र की जिम्मेदारी है और ज्यादातर मामलों में राज्यों की। इन्हीं जिम्मेदारियों में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल न होने के कारण टकराव होता है और जिसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है।

सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे टीबी, एचआइवी, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के पास जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं नीतियों को सुचारु रूप से बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा एवं तकनीकी विशेषज्ञ हैं। दूसरी ओर राज्यों के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को स्वतंत्र रूप से आकार देने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के पास बजट, संसाधन, शोध एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपार संभावनाएं रहती हैं, जबकि प्रदेश सरकारें इन मामलों में काफी पीछे रह जाती हैं। जन स्वास्थ्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता जरूर है, लेकिन वह प्राथमिकता में नहीं रहता।

केंद्र ने संवैधानिक दायित्व की अस्पष्टता के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों का निर्धारण करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। लोक स्वास्थ्य को विशेष रूप से राज्यों के अधिकार तक सीमित करके संविधान जमीनी हकीकत की अनदेखी करता है। राज्यों में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने, जांच सुविधा, उपचार सुविधा, बीमारियों से बचाव के तरीके, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा शर्तों में से किसी में भी एकरूपता देखने को नही मिलती। स्पष्ट है कि इससे तालमेल बैठाने में कठिनाई होती है। कई राज्यों में चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य, दो अलग-अलग विभाग होते हैं, जिनके बीच में कोई तालमेल नहीं होता। ऐसे में यह बिल्कुल उचित समय है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में संवैधानिक शक्ति के वितरण पर फिर से विचार किया जाए और एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिससे राज्य और केंद्र सहकारी भाव से काम कर सकें। इस पर एक बहस शुरू हो और जनता के बेहतर एवं समग्र स्वास्थ्य के लिए 'वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी' पर विचार किया जाए। यह और भी उचित होगा कि जन स्वास्थ्य के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में डालने की पहल हो।

हाल में भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई है। इसमें और 13वें स्वास्थ्य संबंधी कॉमन रिव्यू मिशन के निष्कर्षों से यह साफ जाहिर हुआ कि बड़े शहरों एवं जिला अस्पतालों में तो स्वास्थ्य ढांचा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं काफी अच्छी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन सबका बहुत अभाव है। इसीलिए यह अनुशंसा की गई कि ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए संभावनाएं विकसित की जाएं। 15वें वित्त आयोग को सलाह देने के लिए गठित स्वास्थ्य पर एक उच्चस्तरीय समिति ने केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को संतुलित करने के लिए जन स्वास्थ्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में करने का सुझाव दिया था। यह सुझाव इस मकसद से दिया गया कि राज्य केंद्र की स्वास्थ्य नीति एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसके साथ ही ऐसे तरीके अपनाएं जाने चाहिए, जिससे राज्यों की स्वायत्तता भी बनी रहे।

2014 में भारतीय सुरक्षा संघ बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संवैधानिक सिद्धांतों को राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता के साथ क्षेत्रीय विविधता के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। सहकारी संघवाद, विधायी विषयों विशेष रूप से जन कल्याणकारी विषयों के अनुरूप शासन ढांचे को सक्षम करने की आवश्यकता है। कोरोना ने हमें दिखाया है कि वर्तमान संवैधानिक ढांचा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विषय पर सहकारी संघवाद को कैसे बाधित करता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखना विकेंद्रीकरण की अवधारणा के लिए विरोधाभासी नहीं होगा, क्योंकि इस अवस्था में राज्यों को केंद्र से सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु वित्त के लिए बेहतर सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करेगा और उन्हें यह अवसर देगा कि वे अनुचित आवंटन के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा सकें। यह बदलाव राष्ट्रीय लक्ष्यों का अनुपालन करते हुए राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में सक्षम होगा। यद्यपि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संवैधानिक ढांचे को फिर से आकार देने की प्रक्रिया राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से भरी हुई है, लेकिन कोरोना के प्रकोप ने हमें अहसास दिलाया है कि यह सही समय है जब हम इस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

तालमेल से बनेगी बात

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन पॉलिसी पर अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि महामारी से कैसे निपटना है, यह कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। सरकार की दलील है कि चूंकि कोर्ट की इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए उसकी दखलंदाजी, नेक इरादों के बावजूद बेहद गंभीर नतीजों को जन्म दे सकती है। सिद्धांत रूप में केंद्र सरकार के इस रुख से असहमत होना मुश्किल है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र बंटे हुए होते हैं और यह स्थिति हमेशा अच्छी मानी जाती है कि तीनों अपना-अपना काम पूरी निष्ठा से करते हुए दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने से बचे रहें। आम तौर पर ऐसा होता भी है। समस्या कुछ खास स्थितियों में होती है, जब या तो तीनों में से कोई अंग अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाता या फिर किसी का दायित्व बोध उसे उस मामले में भी कुछ कहने-करने को मजबूर करता है, जिसे दूसरा अंग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मानता है। मौजूदा मामला इसी दूसरी श्रेणी का है, जिसमें कोरोना की बेकाबू हुई दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सिजन और दवाओं के अभाव में असहाय देख न्यायपालिका को लगा कि वह मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। वैक्सीन की कीमतों से जुड़े मौजूदा मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सुओमोटो सुनवाई शुरू की, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसे अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं है। उसने यह साफ कर दिया था कि उसका इरादा किसी भी रूप में सरकार की नीति की जगह अपनी नीति देने का नहीं है। हां, उसने सरकार की नीति को लेकर कुछ चिंताएं जरूर जाहिर कीं। ये चिंताएं सिर्फ न्यायपालिका की नहीं हैं। समाज के अलग-अलग हिस्से इन सवालों को स्वर देते रहे हैं। उदाहरण के लिए, यह आशंका कई लोगों ने जाहिर की है कि वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों का बुरा असर वैक्सिनेशन कार्यक्रम पर पड़ सकता है। यही नहीं, महामारी के अन्य पहलुओं पर भी सरकार की तैयारी और उसके रिस्पॉन्स को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सरकारी तंत्र मरीजों की जान बचाने में लगे अस्पतालों तक जरूरी सुविधाएं और आवश्यक दवाएं, इंजेक्शन, ऑक्सिजन आदि समय से पहुंचने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, यह तो है ही, इसकी शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के भी उदाहरण देखे गए हैं। ऐसे में अदालतें अगर आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में आगे आती हैं तो अपना कर्तव्य ही पूरा करती हैं। बहरहाल, इसमें संदेह नहीं कि महामारी से कुशलता से निपटना कार्यपालिका की जिम्मेदारी है और संकट के इस दौर में शासन के बाकी सभी अंगों की भूमिका उसे इस जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने में मदद देने की ही हो सकती है,

अदालतों के हस्तक्षेप से सरकारों की कोशिश कामयाब हों और जल्द दूर हों महामारी की कमियां

बाजार, शापिंग मॉल, पर्यटन स्थल आदि में भीड़ बढ़ने लगी। शादी-ब्याह और अन्य सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पहले की तरह होने लगे। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी बरतना और मास्क का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया। यह सब इसलिए और हुआ कि जनता के साथ राजनीतिक वर्ग ने भी सतर्कता का परित्याग कर रैलियां, जलसे करने शुरू कर दिए। देश को इसी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो भूलें हुई उनसे सबक सीखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जल्द से जल्द इतनी संख्या में लोगों को टीके लग जाएं, जो हर्ड इम्युनिटी पैदा करने में सहायक हों। इसी के साथ जनता तब तक सचेत रहे, जब तक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से यह न कह दिया जाए कि कोरोना फिर सिर नहीं उठाएगा।

कोविड महामारी की दूसरी लहर से उपजी स्थितियां संभलने का नाम नहीं ले रही हैं। यह महामारी ऐसा रूप धारण किए हुए है कि यह आकलन करना कठिन है कि अभी और कितने लोगों की जान जाएगी? कोविड महामारी की दूसरी लहर को विकराल रूप धारण किए हुए करीब 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ढांचा करीब-करीब हर राज्य में लचर ही दिख रहा है। इस महामारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार ऑक्सीजन है, लेकिन उसकी किल्लत खत्म होती नहीं दिख रही है। जिन्हें बड़े अस्पतालों में आइसीयू बेड मिल गए हैं उन्हें तो राहत है, लेकिन छोटे अस्पतालों और घरों में आइसोलेट कोरोना मरीज आक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। ऑक्सीजन के अभाव में तमाम मरीजों की मौत हो चुकी है।

हालांकि केंद्र ने हर राज्य का ऑक्सीजन कोटा तय कर दिया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ राज्य अपना कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और वे अदालतों तक पहुंच गए हैं। उच्चतर अदालतें केंद्र को ऑक्सीजन की व्यवस्था करने और संबंधित राज्य का कोटा अपने हिसाब से तय करने में लगी हुई हैं। इस क्रम में वे कभी केंद्र को फटकार लगाती हैं और कभी राज्यों को या कभी उनके प्रशासन को अथवा अस्पताल प्रबंधन को। जैसी किल्लत ऑक्सीजन की है, वैसी ही रेमडेसिविर दवा की। इसके साथ अस्पताल बेड की भी तंगी है। यह तंगी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि प्रतिदिन करीब चार लाख नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें से 5-10 प्रतिशत को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। हमारा स्वास्थ्य ढांचा इतने

अधिक कोरोना मरीजों का उपचार करने में समर्थ नहीं।

अदालतों का दरवाजा खटखटाने का काम राज्य सरकारों के साथ अस्पताल संचालक भी कर रहे हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि वे अदालतों की फटकार या अव्यवस्था के आरोपों से बचने के लिए पेशबंदी के तहत ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि अदालतों के पास भी इस समस्या के समाधान का कोई ठोस उपाय नहीं। लगभग हर दिन उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में स्वास्थ्य संसाधनों की कमी के मामलों की सुनवाई हो रही है। संकट के इस समय उनका हस्तक्षेप करना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी ओर से सरकारों के खिलाफ जैसी तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका औचित्य समझना कठिन है। ये टिप्पणियां फैसलों का हिस्सा तो नहीं बन रहीं, लेकिन सुर्खियां अवश्य बन रही हैं। ये सुर्खियां समस्या के समाधान में सहायक बनने के बजाय शासन-प्रशासन का मनोबल गिराने और उनकी प्राथमिकताओं की दिशा बदलने वाली साबित हो रही हों तो हैरानी नहीं।

अदालतों की ओर से कभी अवमानना की कार्रवाई करने के लिए चेताया जा रहा और कभी सरकारों को शुतुरमुर्ग बताया जा रहा है। यह तल्खी समझ आती है, लेकिन क्या इससे संकट का समाधान हो जाएगा या फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या दो-चार अधिकारियों को जेल भेजने से बात बन जाएगी? सवाल यह भी है कि अगर संकट से जूझ रही नौकरशाही हर वक्त अदालतों की फटकार झेलती रही तो फिर वह समस्याओं का निस्तारण कब और कैसे करेगी? यह सही है कि स्वास्थ्य ढांचे की दुर्दशा के लिए सरकारें ही जिम्मेदार हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जो अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया है, वह रातों-रात दूर नहीं हो सकता। आजाद भारत में ऐसा संकट इसके पहले कभी नहीं आया। बेहतर हो कि अदालतों की ओर से यह देखा जाए कि वे इस तरह हस्तक्षेप कैसे करें, जिससे सरकारों की कोशिश कामयाब हो और उनकी कमियां जल्द दूर हों। अदालतों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक समय अमेरिका और इटली जैसे समर्थ और कम आबादी वाले देशों का स्वास्थ्य ढांचा भी चरमरा गया था।

चूंकि संविधान यह कहता है कि राज्य हर नागरिक के जान-माल की रक्षा करेगा, लिहाजा जब उपचार न मिलने से लोगों की जान जा रही हो तो अदालतों को सक्रिय होना ही पड़ेगा, लेकिन बात तब बनेगी जब उनकी सक्रियता हालात बदलने में मददगार साबित हो। चूंकि संक्रमण की तीसरी लहर आने की भी आशंका है, इसलिए दूसरी लहर से जूझ रही सरकारों को भी और सक्रियता दिखानी होगी। कायदे से उन्हें दूसरी लहर का सामना करने की भी तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन वे इसमें असफल रहीं। यह असफलता केंद्र और राज्यों, दोनों की है, क्योंकि समय रहते न तो आक्सीजन प्लांट लग सके, न अस्पताल बेड बढ़ सके और न ही दवाओं का भंडारण हो सका। ढिलाई सभी सरकारों ने बरतीं, लेकिन अब वे दोषारोपण में लगी हुई हैं। खेद की बात यह है कि राजनीतिक वर्ग संकट का सामना मिलकर करने के बजाय तू तू-मैं मैं कर रहा है। इससे खराब बात और कोई नहीं कि विभिन्न दल और खासकर कांग्रेस संकट समाधान में सहयोगी बनने के बजाय राजनीतिक बढ़त हासिल करने के फेर में दिख रही है।

महामारी की दूसरी लहर के समक्ष सरकारें जिस तरह नाकाम हुई, उसके लिए उन्हें लोगों के आक्रोश का सामना करना ही होगा, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि लापरवाही का परिचय देश की जनता की ओर से भी दिया गया। यह तथ्य है कि आम और खास, सभी लोगों ने उन आदेशों-निर्देशों की परवाह नहीं की, जो कोरोना से बचने के लिए लगातार दिए जा रहे थे। नए साल का आगमन होते ही देश का माहौल ऐसा हो गया, मानों कोरोना चला गया हो। लोगों ने सब कुछ कोरोना काल के पहले की तरह करना शुरू कर दिया।

बाजार, शापिंग मॉल, पर्यटन स्थल आदि में भीड़ बढ़ने लगी। शादी-ब्याह और अन्य सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पहले की तरह होने लगे। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी बरतना और मास्क का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया। यह सब इसलिए और हुआ कि जनता के साथ राजनीतिक वर्ग ने भी सतर्कता का परित्याग कर रैलियां, जलसे करने शुरू कर दिए। देश को इसी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो भूलें हुई उनसे सबक सीखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जल्द से जल्द इतनी संख्या में लोगों को टीके लग जाएं, जो हर्ड इम्युनिटी पैदा करने में सहायक हों। इसी के साथ जनता तब तक सचेत रहे, जब तक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से यह न कह दिया जाए कि कोरोना फिर सिर नहीं उठाएगा।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

राजद सुप्रीमो लालू यादव को मिली बड़ी राहत, डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआइ ने दी क्लीन चिट

पटना । राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद के लिए दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिलने के बाद एक और बड़ी राहत की खबर है। तीन साल पुराने डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआइ ने लालू को शनिवार को क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट सीबीआइ ने अपने स्तर पर प्राथमिक जांच के बाद दी है। इससे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को बड़ी राहत मिली है।

दिल्ली में खरीदी पांच करोड़ रुपये की संपत्ति- बता दें कि लालू यादव पर आरोप था कि साल 2007 में एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पांच करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी थी। यह कॉलोनी डीएलएफ ने तैयार की थी। बाद में 2011 में लालू के बच्चों तेजस्वी, चंदा और रागिनी ने एबी एक्सपोर्ट को चार लाख रुपये में खरीद लिया। इस तरह करोड़ों की संपत्ति लालू परिवार को चार लाख रुपये में ही मिल गई।

लालू यादव को रिश्वत पहुंचाने का लगा था आरोप- इसके बाद आरोप लगे कि एबी एक्सपोर्ट के जरिए डीएलएफ ने लालू को रिश्वत पहुंचाई। यह रिश्वत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट के बदले में दी गई थी। इस मामले में सीबीआइ ने कभी कोई केस दर्ज नहीं किया था। कोर्ट के आदेश पर सिर्फ प्राथमिक जांच की थी। अब चूंकि केस ही दर्ज नहीं था तो न आरोपपत्र दायर हुआ और न ही क्लोजर रिपोर्ट आई है। क्लीन चिट सीबीआइ ने अपने स्तर पर प्राथमिक जांच के बाद दी है।

एक तारीख से यूपी के सभी जिलों में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण

लखनऊ । वैश्विक महाकारी कोरोना वायरस के सेकेंड स्ट्रेन पर अंकुश लगाने के साथ ही थर्ड स्ट्रेन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने इस तैयारी के क्रम में प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक जून से टीकाकरण के अभियान को बढ़ाने का निर्देश दिया है।

प्रदेश में एक जून से सभी जिलों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। जिलों में मीडिया तथा न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए अलग से कैम्प की भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक जून से पूरे प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकारण किया जाएगा। इसको वृहद अभियान के रूप में लिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक टीकाकरण से वंचित न रहे। सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण की सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में अभी तक 23 जिलों में ही 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन की सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसको सभी जिलों तक बढ़ाया गया है। अभी तक इसके लाभ से वंचित रहे 52 जिलों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने चरणवार 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजाम किया। पहले यह अभियान उन सात जिलों से शुरू किया गया, जहां पर सर्वाधिक एक्टिव केस थे। इसके बाद इसको बढ़ाकर 18 जिलों यानी मंडल मुख्यालय तक लाया गया। इसके बाद पांच और नगर निगम को जोड़कर 23 तक पहुंचाया गया।

सेनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार, पटना हाईकोर्ट ने 14 को किया है बरी

पटना। बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। इस घटना में एक ही जाति के 34 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार को सबूतों के अभाव में पटना हाईकोर्ट ने सभी 14 आरोपितों को बरी कर दिया था। महाधिवक्ता ललित किशोर ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी राय सरकार को दे दी है। उन्होंने कहा कि सेनारी नरसंहार में जो सबूत हैं वे दोषियों की पहचान के लिए पर्याप्त हैं। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं हुआ। महाधिवक्ता की सिफारिश के बाद अब विधि विभाग उसकी समीक्षा करेगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बिहार: किसान सलाहकारों के मानदेय में हजार का इजाफा, सेवाकाल में मौत पर आश्रितों को मिलेंगे चार लाख

पटना । बिहार सरकार ने कोरोना काल में किसानों के मददगार किसान सलाहकारों के मानदेय और सुविधाओं में वृद्धि कर दी है। अब प्रतिमाह मानदेय के रूप कृषि सलाहकारों को एक हजार रुपये अधिक यानी 13 हजार रुपये मिलेंगे। यह लाभ पहली अप्रैल से मिलेगा। अब सेवाकाल में मौत होने पर आश्रितों को चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान (मुआवजा) भी दिया जाएगा।

इसके पहले 2017 में हुई थी वृद्धि- किसान सलाहकारों के मानदेय में अंतिम बार 2017 में वृद्धि की गई थी। तब उनका मानदेय आठ हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया गया था। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत स्तर पर किसान केंद्र चलाने के लिए कृषि विभाग ने राज्य योजना के तहत प्रगतिशील किसानों का किसान सलाहकार के रूप में चयन किया था। इनका प्रमुख काम कृषि विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार, सत्यापन, मिट्टी की जांच करवाना, खेती के लिए किसानों को बैंक से लोन दिलाने में मदद करना है। सरकार द्वारा तय प्रविधान के तहत तो प्रत्येक पंचायत पर एक किसान सलाहकार की तैनाती होनी है। पर, वर्तमान में आठ हजार पंचायतों की तुलना में 6327 किसान सलाहकार कार्यरत हैं।

एक अरब से अधिक राशि का आवंटन स्वीकृत- सरकार ने मानदेय के भुगतान के लिए एक अरब दस लाख 39 हजार रुपये की मंजूरी दे दी है। वहीं, किसान सलाहकारों की यदि सेवाकाल के दौरान मौत होती है तो अनुग्रह अनुदान के भुगतान की पूरी प्रक्रिया जिला स्तर पर ही संपन्न होगी। भुगतान की निकासी एवं व्ययन, प्रक्रिया की जांच से लेकर भुगतान तक की जिम्मेदारी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को दी गई है। इस तरह से अब प्रतिमाह मानदेय के रूप बिहार में कृषि सलाहकारों को एक हजार रुपये अधिक यानी 13 हजार रुपये दिए जाएंगे।

पंजाब पुलिस ने पेश की मिसाल, ग्रीन कोरिडोर बना कोरोना मरीज को 40 मिनट में पहुंचाया जालंधर से लुधियाना

जालंधर । कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में जालंधर पुलिस ने शनिवार को एक शानदार मिसाल पेश की है। एक कोरोना मरीज की हालत गंभीर होने पर पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए उसे सिर्फ 40 मिनट में जालंधर से लुधियाना पहुंचाया है। मामला शहर के एक निजी अस्पताल से जुड़ा है। यहां बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले अंकुर गुप्ता को भर्ती करवाया गया है। अंकुर को 5 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पठानकोट रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसके बाद डॉक्टरों ने अंकुर के लिए ईसीएमओ बेड की जरूरत बताई। दरअसल इस बेड में जो मशीन लगी होती हैं, वे फेफड़ों में बाईपास कर सीधा ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाती है। स्वजनों ने इस बेड की काफी तलाश की। इसके बाद उन्हें लुधियाना के एक निजी अस्पताल में यह बेड मिल गया। फिर, मामले की जानकारी जालंधर पुलिस को भी दी गई। इस पर शुक्रवार को हरकत में आई पुलिस ने अस्पताल में अपनी एस्कॉर्ट भेज दी लेकिन मरीज की हालत गंभीर होने के चलते मरीज को उस समय रेफर नहीं किया जा सका।

लाडोवाल टोल प्लाजा से फोर्टिस अस्पताल तक किया एस्कार्ट- डॉक्टरों की काफी जद्दोजहद के बाद जब मरीज की हालत में थोड़ा सुधार हुआ तो थाना डिवीजन आठ के प्रभारी रविंद्र कुमार और एक एस्कॉर्ट जिप्सी उनके आगे लगी। यहां से पुलिस की जिप्सी और एंबुलेंस को लुधियाना के तरफ रवाना किया गया। इस दौरान एसपी गुरुदेव सिंह जी मौजूद रहे। लाडोवाल टोल प्लाजा से लेकर फोर्टिस अस्पताल तक मरीज को एस्कॉर्ट किया गया। पूरे रास्ते में इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं भी ट्रैफिक के चलते एंबुलेंस न रुके। पुलिस के प्रयास से मरीज को करीब 40 मिनट के अंदर ही लुधियाना के अस्पताल तक पहुंचा दिया गया।

यूपी के नवनिर्वाचित प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह 25 व 26 को, वर्चुअल होगा शपथ ग्रहण

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में गांव के सरकार की गठन के लिए दो मई को परिणाम आने के बाद भी शपथ लेने का इंतजार करने रहे विजेताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्राम प्रधान के पद का चुनाव जीतने वालों का अब इंतजार समाप्त हो गया है। इनको शपथ दिलाने का इंतजाम हो गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना दो, तीन व चार मई तक चली और गांवों को उनकी नई सरकार मिल गई। पंचायती विभाग ने प्रस्ताव में 12 मई को शपथ ग्रहण की बात की थी, लेकिन गांवों में तेजी से फैल रहे कोरोना के मद्देनजर हर कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी।

उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव संपन्न हुए। इसके बाद वोटों की गिनती 2 मई को शुरू हुई। 20 दिन बाद ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। इसी के साथ शनिवार यानी आज ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तारीखों की भी घोषणा की गई है। 25 व 26 मई को इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश का पंचायती राज विभाग इन सभी को 25 व 26 मई को शपथ दिला देगा। इसके बाद भी बड़े लोग इससे वंचित रहेंगे। इनमें बड़ी संख्या में वह लोग हैं, जिनकी परिणाम आने से पहले ही कोरोना संक्रमण या फिर अन्य कारण से मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही परिणाम में विवाद होने के कारण भी बड़ी संख्या में लोग ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के बाद भी शपथ लेने से वंचित रहेंगे।

प्रदेश शासन ने 25 से 26 मई को ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथि तय करते हुए वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग या वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाने के निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शपथ दिलाने की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लें। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को 24 मई को ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद संगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को आयोजित होगी।

अपर मुख्य सचिव ने कहा 58,176 प्रधानों सहित 731813 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ लेना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत इतनी बड़ी संख्या में ब्लॉक पर शपथ समारोह कराना सम्भव नहीं होगा। इसी कारण वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी के नामित अधिकारी वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग या वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलवाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि अपने ग्राम पंचायत में ही पंचायत घर, सामुदायिक भवन या ग्राम पंचायत क्षेत्र के कॉमन सर्विस सेंटर में शपथ लेंगे।

उन्होंने कहा कि उन ग्राम पंचायतों को अधिसूचित नहीं किया जाएगा, जहां से ग्राम प्रधान व कम से कम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं। अर्थात सदस्य का दो तिहाई होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शपथ ग्रहण से जुड़ी जानकारियां निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय से उपलब्ध करा दें। उन्होंने बताया कि वर्चुअल शपथ के लिए लैपटॉप आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव गण सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि शपथ पत्र की पर्याप्त प्रतियां रखी जाए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय तथा क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए विभिन्न माध्यमों से भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शपथ ग्रहण के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाए।

जीतकर भी प्रयागराज के 911 प्रधान नहीं ले पाएंगे - प्रयागराज में विजेता 1522 ग्राम प्रधानों में से 911 शपथ नहीं ले पाएंगे। सिर्फ 611 को ही शपथ दिलाई जाएगी। जिले की 1540 ग्राम सभाओं में महज 611 प्रधान ही शपथ ले सकेंगे। शेष 911 इनका शपथ ग्रहण समारोह बाद में ही कराया जाएगा। प्रयागराज जिले में 1540 ग्राम सभा में पहले चरण मे 15 अप्रैल को मतदान हुआ। इसके बाद प्रधान के तो सभी पद भर गए, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य के 19 हजार से अधिक पदों में से लगभग 10 हजार पद रिक्त हैं। अब पंचायत के लिए शपथ ग्रहण का समय 26 जून तक तय है। यहां लगभग सभी ब्लॉक में कुछ न कुछ ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण फंसेगा। बहादुरपुर ब्लॉक में एक दर्जन से अधिक प्रधान ऐसे हैं, जिनका शपथ ग्रहण फिलहाल संभव नहीं है। डीपीआरओ, रेनू श्रीवास्तव ने बताया कि कोरम पूरा न होने के कारण 1540 ग्राम सभाओं में से महज 611 प्रधान ही फिलहाल शपथ ले सकेंगे। शेष का शपथ ग्रहण अगले चरण में संभव होगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में 15 से 29 अप्रैल के बीच में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन कराया गया था। पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को, दूसरे का 19, तीसरे का 25 और चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को हुआ था। दो मई को मतगणना थी, जो कि चार तक चली थी।

केडीए में हुई बैठक में सीएम बोले... कानपुर में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बनेगा सेंटर

कानपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कानपुर और इटावा में कोरोना को लेकर वर्तमान हालात और तीसरी लहर की तैयारियों के इंतजाम देखे। कहा कि प्रदेश में 10 साल से छोटे बच्चों के अभिभावकों का जल्द टीकाकरण कराया जा रहा है, जिससे तीसरी लहर में सबको सुरक्षित रखा जा सके। इससे बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में तीमारदारी में लगे माता-पिता बचे रहेंगे। अखिलेश का बिना नाम लिए कहा, वैक्सीन खराब बताने वाले अब लगवाने की बात कह रहे हैं। वहीं, ब्लैक फंगस के इलाज का सेंटर कानपुर में बनेगा। कानपुर में केडीए सभागार में बैठक के दौरान कहा कि नगर निगम के एक अस्पताल को बच्चों का अस्पताल बनाया जाएगा।

फर्रुखाबाद और कानपुर देहात में खराब वेंटिलेटर नहीं बदलने पर नाराजगी जताई। साथ ही गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (जीएसवीएम) मेडिकल कालेज के प्राचार्य प्रो. आरबी कमल पर नाराज हुए कि जैसी अपेक्षा थी, मेडिकल कालेज ने वैसा काम नहीं किया। इसे तो संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) और किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) की तरह लीडर की भूमिका निभानी चाहिए थी। सवाल उठाया कि 17 सौ बेड होने के बावजूद सिर्फ 350 बेड कोविड के लिए रखना कहां तक उचित है। वहीं, शनिवार को पहली बार इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में कोरोना को लेकर इंतजाम देखने के बाद कहा कि मई के अंत तक दूसरी लहर के खत्म होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार मजबूती के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से 300 आक्सीजन प्लांट लगाकर प्रदेश के प्रत्येक जिले को आक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में 100 पीडियाट्रिक आइसीयू बेड और जिला अस्पतालों में 25 आइसीयू बेड स्थापित किए जाएंगे।

कहा कि प्रदेश के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि एक लाख केस 25 अप्रैल से 10 मई के बीच आएंगे, लेकिन 24 अप्रैल को सर्वाधिक 38 हजार केस आए, जो अब घटकर छह हजार बचे हैं। एक्टिव केस तीन लाख 10 हजार के सापेक्ष घटकर 94 हजार हैं। प्रदेश में एक करोड़ 62 लाख लोगों को निश्शुल्क वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 18 से 44 आयु वर्ग में 23 जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा है। जून में लक्ष्य दोगुना करके अन्य जिलों को शामिल किया जाएगा। हर जिले में मीडिया कर्मियों, जजों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इटावा में एक लाख 20 हजार लोगों के वैक्सीन लगवाने को लेकर प्रशंसा की। कहा कि हर जिले में कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों को भोजन मिलेगा। इसके लिए सांसद, विधायक भी आगे आएंगे। जून से लेकर अगस्त तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्यान्न योजना का राशन 15 करोड़ लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है। दो करोड़ जरूरतमंदों को एक हजार रुपये भत्ता मिलेगा। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट देश में सबसे अच्छा - मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट पहले 17 फीसद था, जो घटकर अब 2.4 फीसद रह गया है। रिकवरी रेट अब 93 फीसद है, जो देश में सबसे अच्छा है। इटावा का पॉजिटीविटी रेट एक समय 30 फीसद था, जो अब घटकर दो फीसद से नीचे आ गया है।

काले झंडे दिखाने की कोशिश, विपक्ष के नेता नजरबंद - मुख्यमंत्री योगी को कानपुर में काले झंडे दिखाने की कोशिश हुई। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने सिर मुंडवाकर विरोध जताया। प्रसपा व कांग्रेस नेता नजरबंद रहे। वहीं, इटावा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मलखान सिंह को नजरबंद रखा गया।

सहारनपुर के इस शहर में जब साइकिल से पहुंचे एसडीएम, धड़ाधड़ बंद हुई दुकानें; मचा हड़कंप

सहारनपुर । जनपद के गंगोह में लाकडाउन के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं कई जरूरी दुकानों के अलावा भी अन्य दुकाने भी खुली रहीं। इसी बीच में इसकी सूचना पर एसडीएम मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद एसडीएम हिमांशु नागपाल ने नगर में लाकडाउन की स्थिति देखा। कई जगहों पर भारी भीड़, बेवजह लोगों का बाहर निकलना व अव्यवस्था का आलम मिला। फिर क्या था साइकिल पर भ्रमण को निकले एसडीएम ने कई की क्लास लगा दी। ऐसा दृष्य देख बाजार में हड़कंप मच गया। धड़ाधड़ दुकाने बंद होने लगी। दुकानदार ताला लगाकर भागने लगे। कुछ ही देर में भीड़ से भरी बाजार वीरान हो गई।

उत्तर प्रदेश में 24 मई तक लाकडान बढ़ाया गया है, जिसमें केवल जरूरी चीजों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद रखने की ही अनुमति है। इसके बावजूद गंगोह में सरकार की गाइड लाइन का लगातार उल्लघंन कर हो रहा है। जहां आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानें भी मौके का फायदा उठा रही हैं तो वहीं बाजारों में ग्राहकों की भीड़ भी आम दिनों की तरह हो रही है। पुलिस ने तीन दिन से अभियान चलाकर ऐसे लोगों को पकड़ा भी था, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को भी नगर का कुछ ऐसा ही हाल रहा। इसी स्थिति का जायजा लेने गंगोह एसडीएम पहुंच हुए थे।

धड़ाधड़ बंद हुई दुकानें

एसडीएम हिमांशु नागपाल अचानक गंगोह पहुंचे व अपनी गाड़ी को छोड़ कर साइकिल लेकर भ्रमण पर निकल पड़े। उनके पीछे पुलिसकर्मी भी रहे लेकिन उन्होंने दूरी बनाए रखी। आरंभ में कुछ लोग उनकी पकड़ में आए लेकिन उनके आने का पता लगते ही धड़ाधड़ दुकानें बंद हो गई। बाजार में पहुंचने पर उन्हें सडकों पर भीड़ दिखाई दी तो उन्होंने कई को पकड़कर क्लास लगा दी। कुछ देर में ही सड़क वीरान हो गई। एसडीएम ने सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। साथ ही पालिका कर्मियों से सैनिटाइजेशन की जानकारी ली।

कहां दो गज की दूरी का तकाजा, यहां तो चल रहा था बाहों में आ जा; पकडे गए छह युवक-युवती

जमशेदपुर । कोरोना काल में दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यह अपील हर माध्यमों से की जा रही है। लेकिन यहां तो दो गज की दूरी के तकाजे को कौन कहे, बाहों में एक-दूसरे को भरने का काम चल रहा था। सूचना पर पुलिस जब एक घर में दाखिल हुइ तो वह भी दंग रह गइ। पुलिस तीन युवक एवं तीन युवतियों को गिरफ्तार कर साथ ले गइ। सबों को बाद में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर का है। जमशेदपुर शहर के बिरसानगर थाना की पुलिस ने जोन संख्या तीन के घर में छापेमारी कर तीन युवती और तीन युवक को पहले हिरासत में लिया। सभी को पुलिस थाना ले गई जहां सभी से पूछताछ की गइ। इसके बाद बजाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस बस्ती के लोगों ने सूचना दी थी कि घर में देह व्यापार का धंधा संचालित हो रहा है। बाहरी लोगों का आना-जाना होता है। इसी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की।

हालांकि, शुरुआत में पुलिस मामले में स्पष्ट रूप से कुछ बयां नहीं कर रही थी। थाना के अधिकारी का कहना था कि तीनों युवक के मोबाइल के कॉल की जांच की गई है। किसी युवक का मोबाइल कॉल युवितयों के मोबाइल पर नहीं मिल रहा है। अगर देह व्यापार के धंधे में शामिल होते तो अवश्य मोबाइल पर बातचीत होती। युवक और युवतियों को थाना में लाकर रखे जाने के बाद शुक्रवार को देर रात तक थाना में भीड़ लगी रही।

हालांकि, बिरसानगर थाना की पुलिस ने जोन संख्या तीन प्रधान कालोनी के घर में शुक्रवार देर रात देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन युवती समेत छह को शनिवार को अदालत में प्रस्तुत किया जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घर के सामने से कार और बुलेट भी पुलिस ने बरामद किए थे। अपर पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि घर में देह व्यापार का धंधा चल रहा था।

पंजाब में 24 मई से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित

चंडीगढ़ । पंजाब के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 24 मई से 23 जून तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषित कर दी गई हैं। यह ऐलान शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने की। उन्होंने कहा कि कोविड -19 महामारी के कारण शैक्षिक संस्थान विद्यार्थियों के लिए पहले ही बंद कर दिए गए थे। अब एक महीने के लिए स्कूल अध्यापकों और अन्य स्टाफ को भी छुट्टियां कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार महामारी के दौरान लोगों की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए लगातार सावधानियां बरतने के साथ-साथ अपेक्षित उपाय कर रही है। विजय इंदर सिंगला ने कहा कोविड के कारण पिछले साल से स्कूल बंद होने के बाद शिक्षा विभाग के अध्यापक मोबाइल एप्लीकेशन और टीवी चैनलों समेत अलग-अलग ऑनलाइन माध्यमों से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस साल भी अध्यापक सिलेबस आनलाइन ही मुकम्मल करने के लिए विद्यार्थियों की हरसंभव सहायता कर रहे हैं। मंत्री ने अध्यापकों से अपील भी की कि वे छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहें और विद्यार्थियों और अभिभावकों को कोरोना वायरस को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकोल की पालना करने संबंधी जागरूक करें।

सुनियोजित तरीके से बंगाल में हिंदुओं पर हो रहा हमला - अद्वैत चरण

रांची । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अद्वैत चरण दत्ता ने कहा कि बंगाल में सुनियोजित तरीके हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा है। बंगाल की गौरवशाली इतिहास को समाप्त करने की साजिश चल रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखने के बाद वर्ष 1946 में बंगाल में हिंदुओं के हुए कत्लेआम की घटना याद आ रही है। बंगाल विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद से ही वहां की महिलाओं, आदिवासी, दलित व अनुसूचित जाति समाज के लोगों को निशाना बनाया गया है।

परंतु इस कठिन परिस्थिति में वहां के हिंदुओं को हमें विश्वास दिलाना होगा की हम उनके साथ हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेकर वहां के पीड़ितों को न्याय दिलवाना चाहिए। वे राष्ट्र सेविका समिति की सेव बंगाल फोरम की ओर से शनिवार को आयोजित कार्यक्रम को आनलाइन संबोधित कर रहे थे। विषय था बंगाल की वर्तमान स्थिति।

उन्होंने कहा कि बंगाल स्वामी विवेकानंद, मां शारदा, रवींद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय जैसे प्रमुख मनीषियों की भूमि है। इसका अपना इतिहास है। परंतु कांग्रेस, वाम दल और टीएमसी के शासन में वोट बैंक की राजनीति के चलते घुसपैठिए और रोङ्क्षहग्या को बसाया गया।

जेहादी शक्ति को बढ़ावा दिया जाने लगा। चुनाव से पहले ममता बनर्जी कहती थी कि खेला होवे और इसी का परिणाम है कि चुनाव परिणाम के बाद हिंदुओं पर कट्टरपंथी मजहबी आक्रमण शुरू हो गया है। कई मंदिरों को तोड़ दिए गए। घर व दुकान को लूटना शुरू कर दिया गया। बंगाल के सात-आठ जिलों में ज्यादा आक्रमण हुए। 10 हजार से अधिक महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं। 3000 से अधिक लोग असम में शरण लिए हुए हैं।

मोगा जिले (पंजाब) में भारतीय वायुसेना के मिग -21 दुर्घटना में मारे गए पायलट अभिनव चौधरी का शव मेरठ में उनके घर पहुंचा

ई-पास मांगने पर कार चालक ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, गिरफ्तार

रांची । चुटिया थाना क्षेत्र में लाला लाजपत राय चौक (सुजाता चौक) के पास एक कार चालक ने ई-पास मांगने पर वहां तैनात पुलिस वाले पर ही अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। रोकने पर गाली-गलौज भी किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित युवक शेखर मिश्रा चुटिया थाना क्षेत्र के ही कृष्णापुरी रोड नंबर एक में हनुमान मंदिर के पास का निवासी है। उसके खिलाफ चुटिया थाने के दारोगा दीपक कुमार राय के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 20 मई की देर रात करीब एक बजे डोरंडा के राजेंद्र चौक से सुजाता चौक की तरफ एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। उस वक्त शहर में चेकिंग अभियान चल रहा था। पुलिस ने उक्त कार को रूकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार रूकने के बजाय तेजी से पुलिस वालों की ओर ही बढ़ाया। पुलिस वाले किसी तरह पीछे हटकर खुद को बचाये।

जब पुलिस ने कार को रोका और चालक से ई-पास की मांग की तो उसने पुलिस पर ही रौब गांठना शुरू कर दिया। गाली-गलौज भी की और कहा कि वह क्यों ई-पास दिखाएगा। वह तब शराब के नशे में धुत था और पुलिस के समझाने पर भी वह गाली-गलौज किया जा रहा था। जब वह नहीं माना तो पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार किया। उसपर सरकारी कार्य में बाधा डालने व लॉकडाउन का उल्लंघन करने से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। चुटिया थाने की पुलिस ने शनिवार को कोविड रिपोर्ट मिलने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और असम विधानसभा के अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी गुवाहाटी में विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए जाते हुए।

कोलकाता के एक कोविड-19 अस्पताल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक मरीज को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित करने के लिए एम्बुलेंस के अंदर ले जाते हुए।

हैदराबाद के एक अस्पताल में काले कवक से संक्रमित मरीज की जांच करता एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता।

एक नजर

कोरोना संक्रमित आसाराम की सेवा के लिए पुत्र नारायण साईं ने लगायी जमानत अर्जी

अहमदाबाद । सूरत की दो युवतियों से दुष्कर्म के मामले में करीब 7 साल से जेल में बंद नारायण साईं ने पिता आसाराम की सेवा के लिए जमानत अर्जी लगाई है। गुजरात उच न्यायालय में दाखिल अपनी अर्जी में नारायण साईं ने कहा है कि मेरे पिता की उम्र करीब 85 साल है तथा वे कोरोना संक्रमित हैं। पिता ने आजीवन आयुर्वेद का ही उपचार लिया है इसलिए उन्हें एलोपैथी का उपचार ठीक नहीं कर पाएगा उनकी मौत भी हो सकती है।

नारायण साईं ने अदालत में बताया कि पिछले 7 साल में वह अपने पिता से नहीं मिला है तथा अब बीमारी की हालत में वह उनकी सेवा करना चाहता है। उच न्यायालय नारायण साईं की जमानत याचिका पर राय सरकार को नोटिस दिया है तथा आगामी 26 मई को सुनवाई होगी। नारायण साईं सूरत की लाजपोर जेल में बंद है। सूरत की दो युवतियों ने साईं पर अहमदाबाद के साबरमती में स्थित आश्रम में उनको बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आसाराम भी इस मामले में आरोपी हैं, जोधपुर पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तारी के बाद साईं गुजरात से भागकर उत्तर भारत की ओर चला गया था। पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के पास दिल्ली हाईवे से गिरफ्तार किया था। एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की जेल में सजा काट रहे आसाराम कोरोना संक्रमित हो गए थे जिनका जोधपुर एम्स में उपचार चल रहा है। जमानत के लिए आसाराम ने भी उच न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर रखी है। आसाराम आयुर्वेद पद्धति से उपचार कराना चाहते हैं इसलिए 30 दिन के लिए जमानत पर छोड़ने की याचिका दाखिल की है। आसाराम बापू को 2018 में दुष्कर्म मामले में कारावास की सजा सुनाई गई थी वे 7 साल से भी अधिक समय से जोधपुर की जेल में बंद है। मई 2020 में भी आसाराम ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी लेकिन तब उनकी याचिका ठुकरा दी गई थी।

सरकारी कर्मचारी आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी की सदस्यता नहीं ले सकेंगे

जयपुर । राजस्थान में कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात-ए-इस्लामी, रेडिकल लेफ्ट, राइट विंगर और आनंद मार्ग जैसे संगठनों की सदस्यता नहीं ले सकेगा और न ही इनके कार्यक्रमों में शामिल होगा। ऐसा करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सरकारी कर्मचारी इन संगठनों के पक्ष में पोस्ट नहीं डाल सकेंगे। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत द्वारा विधानसभा सत्र में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने लिखा कि 18 मार्च, 1981 के परिपत्र के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी इन संगठनों की सदस्यता नहीं ले सकता। यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी इन इनके पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है तो यह राजस्थान असैनिक सेवाएं आचरण नियम,1971 के नियम-7 का उल्लंघन है।

ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ राज्य कर्मचारियों के सेवा नियम 1958 के तहत नोटिस देकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी कर्मचारी इन संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते हैं। कार्मिक विभाग ने साल,1981 में एक परिपत्र जारी कर 17 संगठनों की सूची जारी की थी। इनके कार्यक्रमों में शामिल होने व सदस्यता लेने पर सरकारी कर्मचारियों पर रोक लगाए जाने की बात कही गई थी। ऐसा करने पर सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया था। उल्लेखनीय है कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का मंत्री सदन के अंदर जवाब देते हैं। इसके बाद लिखित जवाब संबंधित विधायक को भेजा जाता है।

ऐसा ही जवाब अब विधायक रोत को भेजा गया है। गौरतलब है कि राजस्थान कांग्रेस की सियासी चिंगारी फैलती ही जा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विश्वस्त वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के इस्तीफे व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी के बयान के बाद अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने दोनों से बात नहीं की। हालांकि तीन दिन बाद इस मसले पर पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि प्रदेश की राजनीति में चौधरी जैसा कोई ईमानदार और वरिष्ठ नेता नहीं है। चौधरी का इस्तीफा देना हम सबके लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। पायलट ने कहा कि चौधरी विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, वे छठी बार विधायक बने।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की छोटी बहन रूपम का उदयपुर में निधन, कहा एक गीत रह गया अधूरा

उदयपुर । कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की छोटी बहन रूपम का शनिवार को उदयपुर में निधन हो गया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी छोटी बहन के लिए प्रार्थना की। आप सभी की दुआओं का बहुत शुक्रिया, किन्तु मेरी छोटी बहन रूपम ने शनिवार सुबह आखिरी सांस ली। उन्होंने यह भी लिखा कि रूपम की मौत से एक गीत जो अधूरा रह गया...। पवन खेड़ा ने अपनी बहन की मौत का कारण नहीं बताया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्वीट से लगता है कि रूपम की मौत कोरोना महामारी की वजह से हुई।

सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर संवेदना जताते हुए लिखा एक प्रिय मित्र और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को उनकी बहन के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। कोविड -19 ने इतने प्रियजनों को छीन लिया है कि यह विनाशकारी है। भगवान उन्हें और परिवार को नुकसान सहने के लिए शक्ति प्रदान करे ।

कांग्रेस के कई सदस्यों और अन्य दलों के नेताओं ने भी रूपम के निधन पर संवेदना जताई हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास, पूर्व सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा, राय विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, पूर्व मंत्री दयाराम परमार, कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व प्रदेश सचिव पंकज शर्मा, पूर्व विधायक एवं मौजूदा प्रधान सजनदेवी कटारा के अलावा भाजपा के स्थानीय नेताओं ने भी रूपम के निधन पर संवेदना जताई है। साइबर टीम उदयपुर संभाग के प्रभारी विनोद जैन ने बताया कि रूपम का अंतिम संस्कार दोपहर दो बजे रानी रोड स्थित श्मशान पर कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि पवन खेड़ा का पैतृक मकान फतहसागर किनारे ओटीसी स्कीम में है। उनके पिता यहां विद्युत निगम में सेवारत थे और पवन खेड़ा युवावस्था में दिल्ली चले गए थे। उनके परिवार के कुछ सदस्य अभी भी यहां रहते हैं।

राजस्थान के गांवों में तेज होगा वैक्सीनेशन अभियान, एक करोड़ डोज खरीदेगी सरकार

जयपुर । राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार अब गांवों में वैक्सीनेशन अभियान पर ज्यादा जोर देगी। गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन के लिए अतिरिक्त टीम लगाई जाएगी। पॉजिटिव केस बड़ी संख्या में मिलने के बाद लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कुछ दिन पहले तक ग्रामीण वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब खुद चलकर स्वास्थ्य केंद्रों में जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा का कहना है कि अब शहरों के बजाय ग्रामीण इलाकों में पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए गांवों में आरटी-पीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन की सुविधा पहले से ज्यादा बढ़ाई जाएगी। प्रदेश की आबादी आठ करोड़ है, इसमें से एक करोड़ 55 लाख 73 हजार लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसमें 31 लाख 48 हजार से अधिक लोगों को दोनों डोज लगी हैं।

वहीं, एक करोड़ 25 लाख के करीब लोगों को पहली डोज लगी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन के लिए सरकार एक करोड़ डोज खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दो दिन पहले ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। दो विदेशी कंपनियों स्पूतनिक और एस्ट्राजेनेको ने प्रदेश में वैक्सीन

सप्लाई करने में दिलचस्पी दिखाई है। चिकित्सा मंत्री का कहना है कि सरकार ने कोविशील्ड की 3.75 लाख और कोवैक्सीन की 2.5 लाख खरीदने का भी ऑर्डर दिया है, शीघ्र ही इसकी आपूर्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जरूरत के मुताबिक, डोज नहीं मिलने के कारण वैक्सीनेशन में परेशानी हो रही है।

सात फीसद डोज खराब हुई

प्रदेश में जनवरी से लेकर अब तक करीब सात फीसद से ज्यादा डोज खराब हुई है। यह केंद्र सरकार द्वारा तय सीमा 10 फीसद से कम है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन, रखने में गड़बड़ी या लोगों को लगाते समय खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा चरू में करीब 40 फीसद वैक्सीन खराब हुई है। हनुमानगढ़ में 24.60 फीसद, जयपुर में 5.68, भरतपुर में 17.13, कोटा में 16.17, चित्तौड़गढ़ में 11.81, जालौर में 9.63, सीकर में 8.83, अलवर में 8.33, धौलपुर में 7.89, अजमेर में 6.75, दौसा में 6.65, सवाईमाधोपुर में 6.43, झालावाड़ में 6.31, बूंदी में 5.81, नागौर में 5.41, बाड़मेर में 5.78, बीकानेर में 5.8, करौली में 4.59, टोंक में 4.36, डूंगरपुर में 3.41, पाली में 2.93, जोधपुर में 2.75, राजसमंद में 2.7, भीलवाड़ा में 1.72, प्रतापगढ़ में 1.36, सिरोही में 1.33 फीसद डोज खराब हुई है। कुल मिलाकर 11.6 लाख डोज खराब हुई है। उदयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और झुंझुंनूं जिलों में वैक्सीन खराब होने की जानकारी सामने नहीं है।

बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा को आरएसएस ने करार दिया हिंदुओं पर हमले की एक सुनियोजित साजिश

कोलकाता । बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने हिंदुओं पर हमले की एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। राष्ट्र सेविका समिति की ओर से बंगाल की वर्तमान स्थिति पर शनिवार को आयोजित सेव बंगाल फोरम (वेबिनार) को संबोधित करते हुए संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अद्वैत चरण दत्त ने कहा कि इस सुनियोजित आक्रमण के पीछे एकमात्र निशाना हिंदू समाज हैं।

उन्होंने कहा कि बंगाल का इतिहास हम सभी जानते हैं, किस तरह स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व व इसके बाद इस धरती के महान क्रांतिकारियों व मनीषियों ने राष्ट्र के लिए अंग्रेजों व मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज उसी बंगाल की संस्कृति व इतिहास को टारगेट किया गया। हमने देखा कि आज बंगाल में हमारा हिंदू समाज कितने कष्ट में हैं।उन्होंने कहा कि हाल में देश के पांच राज्यों में चुनाव हुए। कहीं किसी दल ने सत्ता में वापसी की तो कहीं दूसरे दल भी आए हैं।

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में आई है लेकिन जो परिस्थिति है वह पूरी दुनिया देख रही है।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए दत्त ने कहा कि उन्होंने (ममता) जो चुनाव से पहले खेला होबे (खेला होगा) की बात कही थीं उसके पीछे गहरी साजिश थी।उन्होंने कहा कि यहां 30 साल कांग्रेस ने राज किया। फिर तीन दशक तक कम्युनिस्ट ने राज किया। आज 10 साल से तृणमूल है। सबका लक्ष्य वोट बैंक बनाना था। तीनों दलों ने जेहादी शक्तियों को बढ़ावा दिया। बांग्लादेशियो व रोहिंग्या घुसपैठियों को घुसा कर हिंदुओं के खिलाफ एक नए तरह का आक्रमण शुरू किया गया।

चुनाव नतीजे के आज 22 दिन हो गए हैं लेकिन सुनियोजित आक्रमण का सिलसिला चल ही रहा है। आज भी हजारों हजार लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। असम, झारखंड व ओडिशा तक में लोग शरण लिए हैं। कूचबिहार से लेकर गंगासागर तक हिंदुओं के सैकड़ों घर जला दिए गए, उन्हें लूट लिया गया। इनमें ज्यादातर पिछड़े व गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय के परिवारों को निशाना बनाया गया। मां दुर्गा व मां काली की धरती पर हमारी हजारों माताओं व बहनों पर हमला किया गया। करीब 10,000 महिलाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि एक महिला सीएम के राज में इतनी महिलाओं पर हमला व अत्याचार हुआ, लेकिन उन्हें कोई वेदना नहीं हुई।

सात -आठ जिलों में ज्यादा हमले हुए- उन्होंने कहा कि सात - आठ जिलों में ज्यादा आक्रमण हुआ। इनमें पूर्व बर्द्धमान, बीरभूम, उत्तर व दक्षिण 24 परगना, कूचबिहार व हुगली प्रमुख हैं।31 कार्यकर्ताओं की अब तक हत्या कर दी गई। छह मंदिरों को भी तोड़ा गया है। दत्त ने कहा कि यह राजनीतिक संघर्ष व राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं है बल्कि हिंदुओं से जेहादियों का मुकाबला है। उन्होंने मीडिया की भी भूमिका की आलोचना की जो हिंसा की खबरों को पेश नहीं कर रही है।दत्त ने केंद्र सरकार को भी आगाह करते हुए खासकर भारत- बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि हिंदुओं को न्याय दिलाने व उनकी घर वापसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम सभी हिंदुओं को एकजुट भी करेंगे। इस वेबिनार में देशभर से महिला स्वयंसेविका जुड़ी थीं।

राजस्थान में कोरोना के 6103 नए मामले और 115 लोगों की मौत

जयपुर । राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में पिछले चार दिन से लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में संक्रमण की दर में करीब पांच फीसद की गिरावट आई है। प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में संक्रमण की दर 23 फीसद थी, जो अब 18 फीसद से भी कम हो गई। पॉजिटिव केस कम आने के साथ ही मृतकों की संख्या भी कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,103 नए संक्रमित मिलने के साथ ही 115 लोगों की मौत हुई है। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या एक लाख 22 हजार 330 है। शनिवार को 15,464 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। अब तक कुल 7,590 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने के साथ ही नौ लाख नौ हजार 521 संक्रमित मिले हैं। शनिवार को सबसे ज्यादा 1900 संक्रमित जयपुर जिले में और सबसे कम नौ जालौर जिले में मिले हैं।

प्रदेश के 33 में से 11 जिलों में दो अंकों और 21 जिलों में तीन अंकों में संक्रमित मिले हैं। जयपुर के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव 401 केस अलवर जिले में मिले हैं। चिकित्सा विभाग के अनुसार, शनिवार को जयपुर में 21 और जोधपुर में 11 लोगों की मौत हुई। अजमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू में तीन-तीन,अलवर, बीकानेर, डूंगरपुर व पाली में सात-सात, बाड़मेर, कोटा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर में एक-एक, भरतपुर, जैसलमेर में पांच-पांच, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी व नागौर जिलों में दो-दो, हनुमानगढ़ु में छह, सीकर में चार, हनुमानगढ़ में आठ लोगों की मौत हुई। वहीं, सिरोही, श्रीगंगानगर व बारां में एक भी मौत नहीं हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पॉजिटिव केसों में कमी लॉकडाउन के कारण हुई है। लोग घरों से नहीं निकले तो संक्रमण कम फैला। अब सरकार रविवार तक नई गाइड्लाइन जारी करने की तैयारी कर रही है। पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन की अवधि 24 मई को सुबह पांच बजे समाप्त हो रही है।

नकली पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट करने के आरोप में दो गिरफ्तार

उदयपुर । लॉकडाउन में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से लूटपाट कर रहे दो युवकों को जिले की झल्लारा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनसे एक युवक से छीना मोबाइल, नौ हजार रुपये नकद बरामद किए। झल्लारा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ युवक पुलिसकर्मी बनकर लोगों से लूटपाट कर रहे हैं। इस पर झल्लारा थानाधिकारी ने सहायक उप निरीक्षक सलीम खां के साथ पुलिस टीम को सादा वर्दी में तैनात किया। इसी दौरान जैताणा पानगामड़ा मोड पर दो युवक राजस्थान पुलिस के लोगो वाली सफेद टीशर्ट पहने वहां सक्रिय थे। वह वहां से गुजर रहे लोगों को रोककर उनसे पैसा वसूली में जुटे थे। वह लॉकडाउन के दौरान खुली दुकानों के संचालकों से भी पैसा वसूली कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों युवक सेमारी बड़ावली गांव के चुन्नीलाल सुथार तथा गोवर्धन सुथार थे।

उन्होंने स्वीकार किया कि वह पिछले कुछ दिनों से इसी तरह फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट में कर रहे थे। थानाधिकारी मनीष चारण ने बताया कि जैताणा निवासी शंकरलाल की ओर से दोनों युवकों के खिलाफ फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट का मामला दर्ज किया है। उनके कब्जे से पांच हजार रुपये, लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने बारां गांव के एक घर से नकली पुलिसकर्मी बनकर चार हजार रुपये नकद लूटे थे। इसी तरह लाउवा मोड पर एक बाइक सवार से एक मोबाइल तथा पांच हजार रुपये छीन लिए थे।

शादी से पहले दूल्हा गायब- उदयपुर के सवीना क्षेत्र के एक परिवार में शादी के एक दिन पहले दूल्हे के गायब होने से हड़कंप मच गया।

गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत से पूछा, राजस्थान में 11.5 लाख डोज की बर्बादी का जिम्मेदार कौन

जोधपुर । राजस्थान में 11.5 लाख कोरोना वैक्सीन डोज बर्बाद होने पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा कि इस बर्बादी की जवाबदेही कौन लेगा? गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार कहा कि कोरोना वैक्सीन की एक डोज खराब करना एक जिंदगी को सुरक्षा कवच से वंचित करने जैसा है, लेकिन जिन्हें जान से खेलने की पुरानी आदत है वो कहां सुधरेंगे? अब तक राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की 11.5 लाख डोज बर्बाद की जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी डालते हैं। मैं पूछता हूं कि इस बर्बादी की जवाबदेही कौन लेगा? यह तो आपराधिक कृत्य है, जिसकी

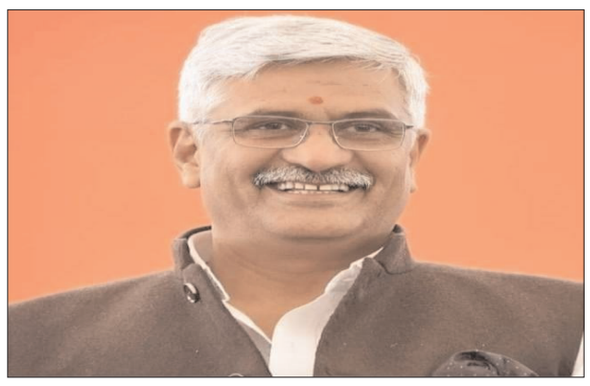

अनदेखी नहीं की जा सकती। यह जनता की जिंदगी का सवाल है। जवाबदेह को सामने लाना भी गहलोत जी की जिम्मेदारी है, अन्यथा हम यह मान लें कि इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री हैं? मुकुल माधव फाउंडेशन ने शेखावत को सौंपे ऑक्सीजन कंसट्रेटर और चिकित्सकीय उपकरण

ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजीशन ऑफ इंडियन ओरिजन (बीएपीआईओ) मुकुल माधव फाउंडेशन की ओर ऑक्सीजन कंसट्रेटर और चिकित्सकीय उपकरण जोधपुर सांसद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपे गए । इसके अलावा समाजसेवियो और उद्यमियों की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिए बीस हजार मास्क और सैनिटाइजर सौंपे। माहेश्वरी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप काबरा और पूर्व उप महापौर देवेंद्र सालेचा ने मंत्री शेखावत के निवास पर जाकर ब्रिटिश एसोसिएशन इंडिया फिजीशन ऑफ इंडिया ओरिजन (बीएपीआईओ) मुकुल माधव फाउंडेशन की ओर ऑक्सीजन कंसट्रेटर, मॉनिटर और चिकित्सकीय उपकरण सौंपे। इसी प्रकार समाजसेवी एवम् उद्यमी सोहन भूतडा, संदीप काबरा, देवेन्द्र सालेचा, जय प्रकाश अग्रवाल, रोहित कालानी, संदीप सिंघवी और भरत कानूनगो ने कोविड केयर सेंटर में जाकर बीस हजार मास्क और सेनेटाइजर सौंपे। यह ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किए जाएंगे। इस दौरान अनेक पार्षद मौजूद रहे।

बार्ज पी-305 के कप्तान पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

मुंबई । मुंबई पुलिस ने सोमवार शाम को अरब सागर में डुबे बजरे (बार्ज) पी-305 के कप्तान राकेश बल्लव सहित कुछ अन्य के विरुद्ध गैरइरादन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। चक्रवाती तूफान टाक्टे की तेज हवाओं व ऊंची लहरों के कारण उक्त बजरे के डूबने से 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस मामले में मुंबई के यलो गेट पुलिस थाने में बार्ज पी-305 पर सवार रहे चीफ इंजीनियर रहमान हुसैन शेख के बयान के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। सोमवार देर शाम बजरे के डूबने के समय रहमान शेख भी उसी बजरे पर सवार थे। बजरे पर सवाल अन्य लोगों के साथ वह भी लाइफ जैकेट पहन कर समुद्र में कूद गए थे। कई घंटे तैरने के बाद उन्हें नौसेना ने बचा लिया था। फिलहाल वह मुंबई के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं।

गुरुवार को उनका बयान सामने आने के बाद यलो गेट पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 304(2), 338, तथा धारा 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह बजरा ओएनजीसी की तरफ से काम कर रही कंपनी एफकान का था, जिस पर तूफान आने के समय 261 लोग सवार थे। इनमें से 186 को बचाया जा चुका है और 51 के शव ढूंढे जा चुके हैं। 24 लोग अभी भी लापता हैं। चीफ इंजीनियर रहमान शेख के अनुसार 14 मई को तूफान की चेतावनी मिलने के बाद उन्होंने जहाज के कप्तान से बजरे को सुरक्षित स्थान पर ले चलने को कहा था, लेकिन कप्तान ने कहा कि तूफान के दौरान हवार की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे से ऊपर नहीं जाएगी, और तूफान कम से कम 120 समुद्री मील दूर से निकल जाएगा। जब 16 मई की शाम से तूफान ने गति पकड़ी तो हवा की रफ्तार 110 किमी. प्रति घंटे से भी यादा थी और समुद्र में आठ से 10 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थीं।

रहमान शेख के अनुसार, इतनी तेज हवा के कारण ही बजरा अपना लंगर तोड़कर निकट स्थित तेल कुएं के प्लेटफार्म से जा टकराया और उसमें छेद हो गया। जब कप्तान को खतरे का अहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। बजरे पर बचाव के लिए रखे 16 में से 14 राफ्ट भी पंचर थे। नहीं तो काफी लोग उसपर तैरकर अपनी जान बचा सकते थे। रहमान शेख ने गुरुवार को एक अखबार से बात करते हुए कहा था कि यदि कप्तान ने सही समय पर उनकी बात सुन ली होती और बजरे पर रखे राफ्ट पंचर नहीं होते, तो इतने लोगों की जान न जाती।

ओएनजीसी की ओर से उसके हीरा आयल रिग के निकट काम कर रही इंजीनियरिंग कंपनी एफकान्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. ने भी अपने एक बयान में कहा है कि तूफान की सूचना मिलने के बाद उसकी ओर से समुद्र में काम कर रहे अपने सभी कर्मचारियों को सूचित किया गया था कि वे अपने-अपने कार्यस्थल को सुरक्षित कर स्वयं भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। इसके बावजूद तूफान आने से पहले पी-305 के कप्तान ने तट की ओर जाने के बजाय अपने बजरे को सिर्फ 200 मीटर हटाकर तेल कुएं के और नजदीक कर लिया। क्योंकि उसे तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटे से अधिक रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन तूफान आने के दौरान हवा की रफ्तार 110 किमी प्रति घंटे से भी यादा रही, और बजरा तेल कुएं से ही जा टकराया। जिसके कारण उसमें छेद हो गया और कुछ घंटे बाद ही वह डूबने लगा। जिसके कारण 50 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

हंसल मेहता की फिल्म में यह किरदार निभाएंगे कार्तिक आर्यन!

कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के उभरते हुए सितारों में से एक है। काफी कम समय में उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली है। वह लगातार नई फिल्में साइन करते जा रहे हैं। खबर है कि उन्होंने हंसल मेहता के निर्देशन वाली अगली फिल्म और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की एक फिल्म साइन की है। खबरों के मुताबिक, हंसल की आने वाली फिल्म पूरी तरह कमर्शल होगी। यह सच्ची घटना पर आधारित एक देशभक्ति की फिल्म होगी। बताया जा रहा है कि हंसल मेहता की आगामी फिल्म में कार्तिक एक एयरफोर्स पायलट की भूमिका में दिखने वाले हैं। यह एक कमर्शियल फिल्म होगी, जिसमें हंसल का टच देखने को मिलेगा। इस फिल्म में एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण देखने को मिल सकता है। वास्तव में यह फिल्म एक असल जिंदगी की घटना पर आधारित होगी। खबरों के अनुसार कार्तिक फिल्म में एक भारतीय वायुसेना अधिकारी की भूमिका को निभाते दिखेंगे। कहा जा रहा है कि कार्तिक को बचाव अभियान का मुख्य पायलट के रूप में फिल्माया जाएगा। वह फिल्म में एक रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि कार्तिक आर्यन से पहले फिल्म 'भुज' में अजय देवगन और 'तेजस' में कंगना रनौट भी इंडियन एयर फोर्स के पायलट के किरदार में नजर आएंगी। इससे पहले पिछले साल ही जाह्नवी कपूर भी 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' में भारतीय वायु सेना की पायलट के करिदार में नजर आई थीं। कार्तिक आर्यन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह इस साल कई फिल्मों में देखा जा सकता है। वह अनीस बज्मी की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 2' को लेकर चर्चा में हैं। वह संजय लीला भंसाली की 'हीरा मंड़ी' में भी नजर आएंगे। कार्तिक अपनी आगामी फिल्म 'धमाका' को लेकर भी सुर्खियों में हैं। वह लक्ष्मण उतेकर की 'लुका छुपी 2' में भी अभिनय करते हुए नजर आएंगे।

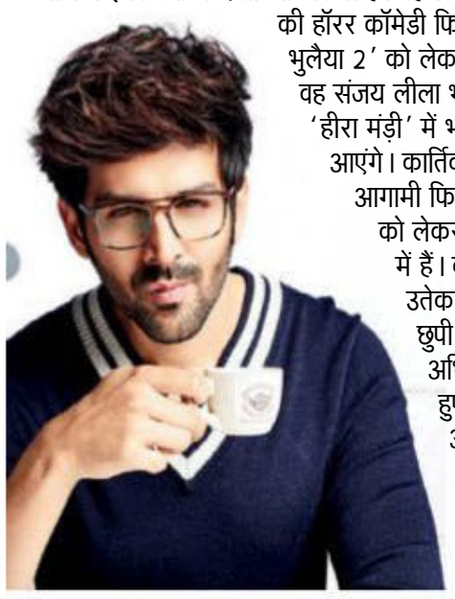

ये रिश्ता क्या कहलाता है का हिस्सा बनना जीवन बनने वाला अनुभव

एक दशक से अधिक समय से सफलतापूर्वक चल रहा राजन शाही का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अभी भी दर्शकों के दिलो-दिमाग पर छाया हुआ है। नायरा गोयनका की प्रमुख भूमिका निभाने वाली शिवांगी जोशी ने बताया किया कि यह शो उनके लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव रहा है।

ये एक आशीर्वाद है

भारतीय टेलीविजन पर इस तरह के एक ऐतिहासिक शो का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मनोरंजन जगत के कुछ बेहतरीन अभिनेताओं, क्रू और निर्माताओं के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है का हिस्सा बनना एक आशीर्वाद है।

सेट पर हर दिन खास

सेट पर हर दिन अद्भुत रहा है। हर दृश्य मेरे लिए खास है। लेकिन अगर मुझे अपने पसंदीदा में से एक को याद करना है, तो वह है कायरा (प्रशंसकों ने शो की मुख्य जोड़ी को कायरा-कार्तिक, जिसे मोहसिन खान और नायरा ने एक साथ निभाया है) के क्षण और ग्रीस और राजस्थान में प्रदर्शन। यह मेरे लिए रोमांचकारी अनुभव था।

कहानी है शो की यूएसपी

शो की यूएसपी कहानी ही है। इसके लिए हमारे गुरु और निर्माता राजन शाही सर को धन्यवाद, जो समझते हैं कि दर्शकों को प्रभावित करने के लिए क्या करना पड़ता है। साथ ही, अद्वितीय कहानी, प्रस्तुति और कलाकारों द्वारा शानदार प्रदर्शन एक असाधारण अनुभव प्रदान करते हैं।

चुनौतियों के बीच कैसे बनाए सकारात्मकता

हर दिन सीखने और याद रखने के लिए एक सबक है, चाहे आप काम कर रहे हों या जब आप छुट्टी पर हों। पिछले मुझे कुछ महीनों के लिए काम से दूर रही
लेकिन मुझे अपने पूरे परिवार से मिलने का मौका मिला। मैंने खुद पर काम किया। घर के कामों में तल्लीन रही और खुद के साथ समय बिताया। ये सबसे अच्छी भावनाएँ हैं जिनका अनुभव हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये अभूतपूर्व समय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है।

राजन शाही मेरे पिता समान

राजन शाही शब्दों से परे हैं, वह मेरे गुरु हैं, मेरे लिए पिता तुल्य हैं, कहानी कहने में महान उत्साही और दूरदर्शी हैं। राजन सर हम सभी को एक साथ रखते हैं, हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं और सेट पर एक स्वस्थ वातावरण भी बनाए रखते हैं। जब आपके पास एक खुश रहने और काम करने के लिए सकारात्मक वातावरण होता है तो सकारात्मक वाइब्स आपके काम में तब्दील हो जाती हैं और स्क्रीन पर भी दिखाई देती हैं।

फिल्म संदीप और पिंकी फरार अमेज़न प्राइम वीडियो पर हुई रिलीज, अर्जुन-परिणीति फिर दिखें साथ

फिल्म निर्माता दिबाकर बनर्जी की संदीप और पिंकी फरार का डिजिटल प्रीमियर अमेज़न प्राइम वीडियो पर आज, 20 मई हुआ। दिबाकर बनर्जी द्वारा निर्मित, लिखित और निर्देशित, संदीप और पिंकी फरार में अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा, जयदीप अहलावत, रघुबीर यादव और नीना गुप्ता मुख्य भूमिकाओं में हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने आज - 20 मई, 2021 को भारत सहित दुनिया भर के 240+ देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर स्टारर थ्रिलर के विशेष डिजिटल प्रीमियर की घोषणा की। संदीप और पिंकी फरार दो पूरी तरह से अलग व्यक्तियों की कहानी है, जिनका जीवन अचानक आपस में जुड़ जाता है। पिंकेश दहिया या 'पिंकी' (अर्जुन कपूर द्वारा निबंधित), एक हरियाणवी पुलिस अधिकारी है, जबकि संदीप कौर (परिणीति चोपड़ा द्वारा निबंधित) कॉर्पोरेट जगत की एक महत्वाकांक्षी लड़की है। विडंबना यह है कि चाक और पनीर की यह जोड़ी एक दूसरे के प्रति अविश्वास, संदेह और घृणा से एकजुट है।

प्राची देसाई को बॉलीवुड में नहीं मिला सम्मान

प्राची देसाई ने टीवी में सफल करियर के बाद फिल्मों की तरफ अपना रुख किया था। उन्हें टीवी की तरह ही फिल्मों में भी पसंद किया गया मगर उन्हें वह सफलता नहीं मिल सकी जिसकी वह हकदार थीं। वहीं अब प्राची देसाई ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। प्राची देसाई ने बताया कि कैसे बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने उनके काम को कभी सम्मान नहीं दिया। वह चाहते थे कि प्राची सिर्फ अपने लुक्स पर ध्यान दें और बड़े पर्दे पर हॉट दिखे। एक्ट्रेस ने कहा, ज्यादातर डायरेक्टर्स ने मुझे अपने लुक्स पर ध्यान देने के लिए कहा। लेकिन मुझे 'सेक्सिस्ट' फिल्में कभी नहीं करनी थी इसलिए मैं उनके ऑफर्स को ठुकराती चली गईं। ऐसे में अब मुझे अच्छे ऑफर्स आने बंद हो गए हैं और इंडस्ट्री में मेरी ऐसी इमेज बना दी गई है जहां लोगों को यह लगता है कि मुझे फिल्में करने में खास दिलचस्पी नहीं है। प्राची ने आगे कहा कि डायरेक्टर्स चाहते थे कि मैं बिना स्क्रिप्ट पढ़े फिल्म साइन कर दूं लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इस वजह से मेरे हाथ से कई फिल्में निकलते चली गईं क्योंकि बॉलीवुड में बड़े डायरेक्टर्स को ना सुनने की आदत नहीं होती। वहीं प्राची ने एक और खुलासा करते हुए बताया कि एक बार उन्हें एक बड़ी बजट वाली फिल्म के लिए ऑफर आया जिसमें उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया। प्राची के इनकार करने के बाद भी फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें दोबारा कॉल किया लेकिन उन्होंने साफ-साफ फिल्म करने से मना दिया। प्राची ने साल 2006 में एकता कपूर के सीरियल 'कसम से' में काम किया था। इस सीरियल से प्राची काफी मशहूर हो गई थीं। इसके बाद 2008 में उन्होंने फरहान अख्तर के ऑपोजिट 'रॉक ऑन' से डेब्यू किया था। इसके बाद प्राची ने लाइफ पार्टनर, वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन, आई मी और मै जैसी फिल्मों में काम किया है।

अपने पहले ही म्यूजिक वीडियो 'वफा ना रास आये' से छाईं अरुशी निशंक

अरुशी निशंक हमेशा संभावनाओं के नए क्षितिज की खोज में रहती हैं, अब वह बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीत रही हैं। टी-सीरीज के बैनर तले नवीनतम संगीत वीडियो 'वफा ना रास आये' से उन्होंने डेब्यू किया है। यह गाना रिलीज़ होने के कुछ घंटों के भीतर ट्रेंड कर रहा था। अरुशी निशंक को अपने प्रशंसकों से सराहना मिल रही है, इस गीत के बाद हेयर स्टाइल और स्टाइलिंग का एक नया चलन शुरू हुआ है। वीडियो बनाने की अपनी यात्रा पर अरुशी ने कहा- यह मेरे लिए वास्तव में चुनौतीपूर्ण था क्योंकि यह मेरा पहला प्रोजेक्ट था और मैं शायद ही तकनीकी भाषा जानता था लेकिन उनके सह-अभिनेता और निर्देशक इतने कॉर्पोरेट और मददगार थे कि वह चीजों को एक में हासिल कर सकती हैं। आसान तरीका है, दूसरी बात यह है कि जनवरी के महीने में कश्मीर में शूट किया गया था, इतने अनुकूल मौसम में शूट करना वास्तव में कठिन था, लेकिन एक साथ वफ़ा ना रास आई की यात्रा आनंदमय थी। उत्तराखंड की रहने वाली अरुशी आम तौर पर युवाओं और खासकर महिलाओं पर काफी प्रभाव छोड़ने में कामयाब रही है। उन्हें भारत सरकार और उत्तराखंड द्वारा कई पुरस्कारों और मान्यताओं के साथ सम्मानित किया गया है। वह सरकार के नेतृत्व में सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के एक सक्रिय प्रवर्तक भी हैं। उन्होंने अपने खुद के कैलिबर और प्रतिभा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित की है। सभी चुनौतियों को समझते हुए, उसने अपने लिए एक जगह बनाई है। वैश्विक ख्याति के एक समर्पित कथक नर्तक होने के अलावा। अरुशी निशंक ने उद्यमिता, कविता और साहित्य, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपने पदचिह्न छोड़ दिए हैं। स्वच्छ नदी गंगा के प्रति जागरुकता जगाना एक आंदोलन रहा है जिसका स्तंभ अरुशी रही हैं। अरुशी निशंक ने 2008 में स्पर्श गंगा अभियान के अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होकर पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान दिया है और गंगा को प्रदूषण और अशुद्धियों से मुक्त करने का संकल्प लिया है। अरुशी पर्यावरणीय चिंताओं और सतत विकास के लिए एक प्रमुख वकील बन गई। अरुशी निशंक ने अंतरराष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसे संयुक्त राष्ट्र का भी समर्थन प्राप्त है। चेयरपर्सन के रूप में, अरुशी सक्रिय रूप से कम लड़की अनुपात और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और महिला सुरक्षा पर और शिक्षा के माध्यम से महिला के लिए आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार के लिए काम कर रही है। काव्य मूर्त दुनिया के बारे में किसी की धारणाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने का एक और लयबद्ध तरीका है। धरती स्वर्ग बनुंगी और कलाम मशाल बन जाए कविता की दो पुस्तकें हैं जो अब तक भारत में प्रकाशित हुई हैं। अरुशी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भारतीय शास्त्रीय कथक प्रतिपादक हैं, जो अपने कला रूप में एक कुशल कलाकार हैं। उन्होंने 16 साल की अवधि में 15 से अधिक देशों में रचना और प्रदर्शन किया है। अरुशी निशंक एक ऐसा नाम है जो लालित्य, स्थापना और कला को अपने साथ रखता है। उनके जैसे बहुआयामी व्यक्ति से हमेशा संभावनाओं के नए क्षितिज तलाशने के लिए जीवन और उत्साह से भरे रहने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने हिमश्री फिल्म्स नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया। वर्ष 2018 में, उन्होंने हिमश्री फिल्म्स के तहत एक क्षेत्रीय फिल्म मेजर निराला का निर्माण किया।

टेस्ट टीम जगह बनाने को लेकर आशान्वित हैं चहल, प्रथम श्रेणी में शानदार रिकार्ड के बाद भी अब तक नहीं मिली जगह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल जल्द से जल्द भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने को लेकर आशान्वित हैं। इतने वर्षों में, चहल ने कई युवा खिलाड़ियों को लाल गेंद के प्रारूप में अपने अवसरों का लाभ उठाते देखा है, लेकिन 30 वर्षीय चहल के लिए टेस्ट क्रिकेट में अभी भी कोई जगह नजर नहीं आ रही है। हरियाणा के स्पिनर का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 31 मैचों में 84 विकेट झटके हैं, लेकिन चयनकर्ता लगातार उन्हें अनदेखा कर रहे हैं। जब भी भारत के फ्रंटलाइन स्पिनर जैसे रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा चोटिल होते हैं, दूसरे खिलाड़ियों को मौका दे दिया जाता है, लेकिन चहल को नहीं।

वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, शाहबाज नदीम और अक्षर पटेल ने वर्ष 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला। यहां भी चहल को मौका नहीं मिल पाया। युजवेंद्र चहल ने अपने टेस्ट करियर को लेकर स्पोर्ट्स तक से बात की और कहा कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद टेस्ट टीम में आने की उनकी संभावना है। उन्होंने कहा जाहिर है, आप सफेद जर्सी पहनना चाहते हैं। अगर कोई आपको टेस्ट खिलाड़ी कहे तो इससे बड़ी कोई तारीफ नहीं है। पिछले 3-4 सालों में मैंने 10 प्रथम श्रेणी मैचों में 50 विकेट चटकाए हैं, जिनमें से दो इंडिया ए गेम्स रहे।

अश्विन और जडेजा पिछले पांच से छह वर्षों के दौरान विशेष रूप से घर पर भारत के लिए अभूतपूर्व रहे हैं। टेस्ट में निचले क्रम के बल्लेबाजों का योगदान कितना उपयोगी है, इस पर विचार करते हुए भारतीय चयनकताओं का स्पिन ऑलराउंडरों को पसंद आम बात है। चहल की बल्लेबाजी में असमर्थता भी उन्हें अभी तक टेस्ट टीम में शामिल नहीं किए जाने का एक कारण हो सकता है। सुंदर और पटेल ने अपना डेब्यू किया। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से भारत के लिए असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया।

चहल ने कहा आपने देखा कि अक्षर आए और अच्छा प्रदर्शन किया। अश्विन, जडेजा और कुलदीप पहले से ही यहां हैं। इसलिए आपको लगता है कि 3-4 खिलाड़ी पहले से ही गिनती में हैं और आपके लिए मौका मिलना मुश्किल होगा। खासकर जब वे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। अश्विन भैया ने 400 टेस्ट विकेट पूरे किए और जड्डू पा ने 250 से अधिक विकेट लिए हैं। उन्हें देखकर आपको लगता है कि मौका पाने के लिए आपको और सुधार करना होगा। लेग स्पिनर को आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिए कॉल-अप की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम में शामिल होने की उम्मीद कर रहे थे। चहल ने कहा इस बार मुझे कॉल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हां जब इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया और हमारे कुछ स्पिनर घायल हो गए तब मुझे कहीं ऐसा लगा कि मेरा नाम शायद आ जाए।

मोनाको के मोंटेकार्लो में आयोजित फामूर्ला रेस जीतने के बाद ट्राफी के साथ चीन के झांग।

विलियम्सबर्ग में खेली जा रही गोल्फ प्रतियोगिता के दौरान बॉल को हिट करती बिनाका।

कोरोनो से ठीक हो चुके स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अभी कड़े अभ्यास के लिए फिट नहीं

चेन्नई, (एजेंसी)। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती कोविड-19 से उबरने के बाद भी कड़े अभ्यास के लिए फिट नहीं हैं, क्योंकि वह काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। चक्रवर्ती इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पहले खिलाड़ी थे जिन्हें कोविड-19 के लिये पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों में भी कुछ मामले सामने आए थे इसके बाद लीग को स्थगित कर दिय गया था। चक्रवर्ती 11 मई को कोरोना से उबर गये थे और अभी वह चेन्नई स्थित अपने आवास पर फिटनेस हासिल कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने कहा, मैं अब अच्छा हूं और घर पर ही ठीक हो रहा हूं। कोविड-19 के बाद की परेशानियों के कारण मैं अभी अभ्यास नहीं कर पा रहा हूं। मुझे हालांकि खांसी या बुखार नहीं है लेकिन कमजोरी है।

उन्होंने कहा, गंध और स्वाद का अनुभव कभी कभार होता है लेकिन मुझे जल्द ही अभ्यास शुरू करने की उम्मीद है।उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ सीखा है, उस मैं कोविड-19 से उबर रहे अन्य खिलाड़ियों को बताना चाहूंगा कि वे परीक्षण नेगेटिव आने के बाद कम से कम दो सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करें। चक्रवर्ती ने कहा, इसके साथ ही परीक्षण नेगेटिव आने के बाद भी मेरी सलाह है कि मास्क जरूर पहनकर रखें ताकि आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहें।

चक्रवर्ती ने कहा,कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद सबसे कड़ी चुनौती अपने दिमाग को विचलित होने से बचाना और जो कुछ हो रहा है, उससे ध्यान हटाना था, क्योंकि आप अपने परिवार और टीम के साथियों से दूर अलग थलग रहते हो। मैंने स्वयं को व्यस्त रखने और शांतचितता के लिए ओशो की पुस्तकें पढ़ी।चक्रवर्ती को एक मई को लक्षणों का अहसास हुआ था जबकि वह अभ्यास सत्र के दौरान बहुत जल्दी थकान महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह सब कैसे शुरू हुआ। मैं एक मई को असहज महसूस कर रहा था। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था।खांसी नहीं थी लेकिन हल्का बुखार था और इसकारण मैंने अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया।

चक्रवर्ती ने कहा, मैंने तुरंत ही टीम प्रबंधन को सूचित किया और उन्हें तुरंत ही आरटी पीसीआर परीक्षण की व्यवस्था की। मैं केकेआर के अपने साथियों से तुरंत ही अलग थलग कर दिया गया। इसके बाद मुझे पता चला कि मेरा परीक्षण पॉजिटिव आया है। उन्होंने कहा, इसके बाद मैं स्वयं को लेकर ही नहीं बल्कि देश में जो कुछ हो रहा था उसको लेकर भी चिंतित हो गया।

उक्रेन की मारिया मुजयचूक के पास कैंडीडेट में जगह बनाने का मौका

लंदन, (एजेंसी)। गिब्राल्टर यूके फीडे विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में पहुँचने का एकमात्र रास्ता 8 खिलाड़ियों वाले फीडे कैंडीडेट में जगह बनाना होता है।साथ ही कैंडीडेट में जाने के लिए दो स्थान फीडे महिला ग्रां प्री से तय होते है। कल से दुनिया की 12 दिग्गज खिलाड़ी अंतिम और चौंथे ग्रां प्री सीरीज टूनार्मेंट में खेलेंगी। अब तक सीरीज में सबसे आगे चल रही भारत की कोनेरु हम्पी के कोविड के चलते नाम वापस लेने के बाद अब उक्रेन की मारिया मुजयचूक प्रतियोगिता में शीर्ष खिलाड़ी होंगी और अगर वह टूनार्मेंट जीते,तब कैंडीडेट में जगह बना सकती है। हालांकि कैंडीडेट में स्थान बनाने के लिए रूस की लागनों काटेरयना और जॉर्जिया की नाना दगनिडजे के पास कैंडीडेट मे जगह बनाने के लिए ज्यादा बेहतर मौका है। फिलहाल अब तक हुए तीन ग्रां प्री के बाद दो स्थानों की दौड़ में भारत की कोनेरु हम्पी 293 अंकों के साथ सबसे आगे है, उनके बाद रूस की अलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक 193 अंकों पर तो काटेरयना और नाना 180 अंकों पर है, टूनार्मेंट जीतकर 160 अंक हासिल कर सकती है देखना होगा की क्या ये ऐसा कर पाएँगी। सभी 12 खिलाड़ियों के बीच राउंड रॉबिन आधार पर हर दिन एक मैच खेला जाएगा।

फीफा प्रमुख ने दिए संकेत, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में होगा बदलाव

जेनेवा, (एजेंसी)। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के अध्यक्ष जियानी इंफेनटिनो ने महासंघों की बैठक में आगामी वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बड़े बदलावों के संकेत दिए। फीफा ने पुरुष और महिला विश्व कप का आयोजन हर चार साल के बजाय दो साल में करने के प्रस्ताव का अध्ययन करने पर सहमति जता दी है। सऊदी अरब ने हर दो साल में विश्व कप के आयोजन का प्रस्ताव रखा था। इस तरह का सुझाव इससे पूर्व 20 साल पहले फीफा के तत्कालीन अध्यक्ष सेप ब्लाटर ने रखा था लेकिन तब इस गंभीरता से नहीं लिया गया था। इंफेनटिनो और उनके साथियों ने सुझाव को फिर से जीवंत किया जो कि अधिक अंतरराष्ट्रीय टूनार्मेंटों की वकालत करते रहे हैं। शुक्रवार को महिला और युवा प्रतियोगिताओं की समीक्षा करने पर सहमति जाहिर की।

प्रत्येक दो साल में विश्व कप का आयोजन करने से यूरोपीय फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यूएफा की नेशन लीग प्रभावित होगी। इससे हर चार साल में होने वाली यूरोपीय चैंपियनशिप की व्यावसायिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। इंफेनटिनो ने सुपर लीग जैसी नई परियोजनाओं पर क्लबों के साथ बात करने का भी बचाव किया। इस लीग के कारण यूएफा में पिछले महीने कोहराम मच गया था और आखिर में यह योजना ठंडे बस्ते में डालनी पड़ी थी। फीफा के 211 सदस्य महासंघों की आनलाइन बैठक के दौरान इंफेनटिनो ने कहा कि खेल में यूरोप और दक्षिण अमेरिका का मैदान के अंदर और बाहर का दबदबा समाप्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, पैसे और खिलाड़ियों के कौशल का दबदबा है जो कि खेल के वैश्विक विकास के लिए सही नहीं है। हम इस अनदेखा नहीं कर सकते हैं।

अरिथरन वासीकरन ने रचा इतिहास, टी10 मैच में छ गेंदों पर 6 छक्के जड़े

नई दिल्ली, (एजेंसी)। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में बल्लेबाज के लिए एक ओवर में छह छक्के जड़ना आसान नहीं होता।लेकिन यूरोपियन क्रिकेट सीरीज में बेयर अर्डिगेन बुस्टर टीम की ओर से 34 वर्षीय बल्लेबाज अरिथरन वासीकरन ने कॉल्न चैलेंजर्स के खिलाफ टी10 मैच में एक ओवर में छह छक्के जड़ इतिहास रच दिया है। अरिथरन गैरी सोबर्स, रवि शास्त्री, हर्शल गिब्स, युवराज सिंह और कायरन पोलार्ड के क्लब में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।

वासीकरन ने बेयर बुस्टर की पारी के 5वें ओवर में लगातार छह छक्के जड़े। उन्होंने स्पिनर आयुष शर्मा की पहली गेंद को फुल लेंथ डिलिवरी पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा। आयुष ने दूसरी गेंद को स्टंप पर टारगेट किया लेकिन अरिथरन वासीकरन ने उसे भी छक्के के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। तीसरी गेंद पर अरिथरन ने फिर मिडविकेट पर छक्का जड़ा। आयुष ने चौथी गेंद हाफ वॉली डाली, अरिथरन ने फ्रंटफुट पर बढ़कर फिर छक्का जड़ा। आयुष की अगली गेंद लेंथ बॉल थी और इस पर भी अरिथरन ने सिक्स जड़ दिया। आयुष की आखिरी गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेज इतिहास रच दिया।

अरिथरन ने 25 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली जिसमें सात छक्के और तीन चौके शामिल थे। उन्हें श्रीनिवास नरेशकुमार ने आठवें ओवर में आउट किया। वासीकरन जब मैच में उतरे उस समय वह सबसे अधिक रन बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर थे। लेकिन इस पारी के बाद वह 7 मैचों में 161 रन के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस सीजन 180 के अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। अरिथरन ने 20 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा।

अरिथरन की शानदार पारी की बदौलत उनकी टीम बुस्टर ने 8 विकेट पर 115 रन बनाए। बुस्टर ने सीजन का अपना दूसरा सर्वाधिक टोटल खड़ा किया। इस मुकाबले को बुस्टर ने 52 रन से अपने नाम किया। 116 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कॉल्न चैलेंजर्स टीम 6 विकेट पर 63 रन ही बना सकी। सोबर्स ने साल 1968 में जबकि शास्त्री ने 1985 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यह मुकाम हासिल किया था। हर्षल गिब्स वनडे में वहीं युवराज टी20 में यह कारनामा कर चुके हैं। पोलार्ड ने हाल में टी20 क्रिकेट में यह उपलब्धि अपने नाम की थी। श्रीलंका के थिसारा परेरा ने हाल में क्लब क्रिकेट में ये कारनामा किया था।

कप्तान विराट कोहली को बल्लेबाजी के गुरु सीखने वाले कोच का निधन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। इंग्लैंड दौरे की तैयारियों में व्यस्त कप्तान विराट कोहली के लिए एक बुरी खबर है। कोहली को बचपन में बल्लेबाजी के गुर सिखाने वाले सुरेश बत्रा का निधन हो गया है। कोहली ने शुरूआती दिनों में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी में कोच राजकुमार शर्मा के अंदर ट्रेनिंग ली थी। सुरेश बत्रा अकादमी में सहायक कोच थे। 53 वर्षीय बत्रा ने सिर्फ नौ साल की उम्र में कोहली की प्रतिभा को पहचान लिया था।

सुरेश बत्रा गुरुवार को सुबह की पूजा करने के बाद अचानक ही गिर पड़े, जिसके बाद वो उठ नहीं सके। उन्होंने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, धारीदार टी-शर्ट पहने सुरेश बत्रा, जिन्होंने विराट कोहली को बचपन में कोच किया, गुरुवार को उनका निधन हो गया।वहीं राजकुमार शर्मा ने कहा कि सुरेश बत्रा के जाने से उन्होंने अपना छोटा भाई खो दिया, वहां 1985 से उन्हें जानते थे।

कोहली के सुपरस्टार बनने से पहले राजकुमार शर्मा और सुरेश बत्रा ने ही उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद की थी। कोहली ने इन्हीं के देखरेख में सिर्फ नौ साल में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था।कोहली के अलावा, 2018 अंडर-19 विश्व कप के फानइल में शतक जड़ने वाले मनजोत कालरा को भी बत्रा ने प्रशिक्षण दिया था।

बत्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अकादमी पर आने के बाद विराट स्कूल में अंडर-14 मैच खेल रहे थे।विराट के बल्ले से निकले एक शानदार छक्के को देखक वहां हैरान रह गए थे। बत्रा ने कहा था, हम प्लेमेकर्स अकैडमी के खिलाफ खेल रहे थे, यह मुकाबला मैटिंग विकेट पर था।लड़के ने बड़ी आसानी से गेंद को पिक किया और उसे मिड-विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया।10 साल से भी छोटी उम्र के लड़के के लिए यह एक शानदार शॉट था।

हालेप पिंडली में चोट के कारण फ्रेंच ओपन से हटी

बुकारेस्ट, (एजेंसी)। विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने पिंडली की चोट के कारण शनिवार को फ्रेंच ओपन से हट गई। रोमानिया की 29 साल की यह खिलाड़ी 2018 में रोला गैरों (फ्रेंच ओपन) में चैम्पियन बनी थी। इटैलियन ओपन के दौरान उनकी पिंडली की मांसपेशियों में चोट लगी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें चोट से उबरने में अभी समय लगेगा। फ्रेंच ओपन 30 मई से शुरू होगा। हालेप ने कहा कि एक ग्रैंडस्लैम से हटना एथलीट के रूप में मेरी सभी सोच और आकांक्षाओं के खिलाफ है, लेकिन मेरे लिए सही और एकमात्र फैसला है। हालेप फ्रेंच ओपन में तीन बार की फाइनलिस्ट हैं। उन्होंने पेरिस में 2018 के फाइनल में स्लोएन स्टीफंस को हराकर अपना पहला बड़ा एकल खिताब जीता। उन्होंने कहा कि पेरिस में नहीं जाने की सोच से मुझे दुख होता है, लेकिन मैं अपनी ऊर्जा को ठीक होने, सकारात्मक रहने में इस्तेमाल करना चाहती हूं। मैं जब भी सुरक्षित हो, खेल में वापसी की कोशिश करूंगी। वह विम्बलडन की मौजूदा चैम्पियन हैं। उन्होंने 2019 में इस खिताब को जीता था जबकि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में टनार्मेंट रद्द हो गया था।

इटली में आयोजित एक साइकिल रेस के दौरान प्रतिभागी जीत के मशक्कत करते हुए।

डब्ल्यूवी रमन को कोच के रूप में रिटेन नहीं करने पर नाराज गांगुली

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों के बीच डब्ल्यूवी रमन को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच के पद से हटाने को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जानकारी सामने आई है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भारतीय महिला टीम के कोच के रूप में रमन को रिटेन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आंतरिक रूप से मुद्दे को उठाया है। समझा जाता है कि गांगुली ने पत्रों के माध्यम से औपचारिक रूप से भारत के पूर्व बल्लेबाज रमन को कोच पद से हटाए जाने पर आपत्ति जाहिर की है।

दरअसल क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने कोच पद के लिए रमन के बारे में विचार तक नहीं कर उनकी जगह रमेश पोवार को कोच चुन लिया गया था। गांगुली ने हालांकि पोवार के चयन पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इसपर हैरानी जाहिर की है कि कैसे एक कोच, जिसने टीम को एक अंतरराष्ट्रीय टूनार्मेंट के फाइनल में पहुंचाया था, को पद पर बरकरार नहीं रखा गया है।

यह बात भी सामने आई थी कि टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने कथित तौर पर रमन के बारे में शिकायत की है, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष, जो खुद एक समय क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य थे उन्हें लगता है कि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज के साथ बने रहना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि रमन के कोच रहते हुए ही भारतीय महिला टीम ने 2020 में ऑस्ट्रेलिया में हुए टी-20 विश्व कप के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था, लेकिन टीम मार्च में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज बुरी तरह हार गई थी।

उधर महिला क्रिकेट से जुड़े कुछ लोगों का कहना है, कि गांगुली को मदन लाल, आरपी सिंह और सुलक्षणा नाइक वाली क्रिकेट सलाहकार समिति के फैसले और इसकी कार्यात्मक स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। महिला क्रिकेट से परिचित बीसीसीआई के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि गांगुली को यह खुद पता होना चाहिए कि क्रिकेट सलाहकार समिति एक स्वतंत्र निकाय है। इस बीच हाल ही में बीसीसीआई की ओर से महिला खिलाड़ियों के अनुबंध पर विवाद खड़ा हो गया है।समझा जाता है कि महिला क्रिकेटरों को आवंटित केंद्रीय अनुबंधों को लेकर बीसीसीआई के अंदर कुछ असंतोष है।बीसीसीआई ने ए ग्रेड में तीन खिलाड़ियों टी-20 कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और पूनम यादव को रखा है, जबकि ग्रेड बी में वनडे कप्तान मिताली राज और शेफाली वर्मा सहित 10 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इससे बीसीसीआई में कुछ असंतोष है, लेकिन गांगुली ने कहा कि वह इस चयन के साथ सहज हैं।